वर्ष: 1 अंक: 18

16-31 मार्च 2021 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

विदेशी बाजार में स्वदेशी खिलौना

आत्मनिर्भर भारत की संकल्प यात्रा में नया पड़ाव, अब स्वदेशी खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

"राष्ट्रीय भावना बन गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान"

देश के युवाओं के मन-मस्तिष्क में आत्मनिर्भर बनने की भावना को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' प्रोग्राम में इनोवेशन, वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों के लिए असम और देश के लोगों की प्रशंसा की। संस्कृत में एक अद्वितीय स्पोर्टस कमेंट्री साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को कई भाषाओं की भूमि और संस्कृति का प्रतीक बताया। पेश है इस मासिक रेडियो प्रोग्राम में उनके संबोधन के अंश:

- **क्या है आत्मनिर्भरता: -**आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल सरकारी नीति नहीं हैं, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय भावना है। जिसकी पहली शर्त होती है- अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना। जब देश का प्रत्येक नागरिक स्पिरट ऑफ साइंस को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ता है तो विकास का मार्ग खुल जाता है और देश आत्मनिर्भर भी बनता है।
- **स्वदेशी वस्तुएं:** भारत में बने कपड़े, हैंडीक्राफ्ट का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है।
- **परीक्षा को जीतें:** आने वाले महीनों में हमारे युवा साथियों की परीक्षाएं होंगी। आपको वॉरियर बनना है, वरियर नहीं। आपको हंसते हुए परीक्षा देने जाना है और मुस्कराते हुए लौटना है। मैंने एग्जाम वॉरियर बुक में कुछ नए मंत्र जोड़े हैं। इन मंत्रों से जुड़ी ढ़ेर सारी रोचक गतिविधियां नरेंद्र मोदी एप पर दी हुई है जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में आपकी मदद करेंगी।
- **तेजस की उड़ान:** जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते हुए देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं तो हमारा सिर और ऊंचा हो जाता है।
- **जल संरक्षण:** माघ का महीना विशेष रूप से नदियों और सरोवरों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस साल कुंभ हरिद्वार में मनाया जा रहा है। यह जल संरक्षण के बारे में विचार करने का सर्वश्रेष्ठ समय है।
- **संत रविदास को नमन:** हम संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। वह भयमुक्त थे और उनके विचार हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें खुद को अपने पुराने तौर-तरीकों में नहीं बांधना चाहिए।
- **विज्ञान का इतिहास:** आज (28 फरवरी को) नेशनल साइंस डे भी है, आज का दिन डॉ. सी.वी. रमन द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा, भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जानें, समझें और खूब पढ़ें।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड Scan करें

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 01, अंक: 18 | 16-31 मार्च 2021

संपादक
जयदीप भटनागर,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक
संतोष कुमार
विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,सूचना भवन, द्वितीय तल,नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

अब खिलौना उद्योग में आत्मनिर्भरता की तैयारी

आवरण कथा पहली बार किसी केंद्र सरकार के एजेंडा में शामिल हुआ खिलौना उद्योग। वैश्विक बाजार में सफलता की नई कहानी लिखने की तैयारी। पेज 10-25

फ्लैगशिप योजना...

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का एक साल

पेज 28-29

सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफार्म्स पर अब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा

लंबे समय से शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने तैयार की गाइडलाइन

पेज 8-9

राष्ट्र के विकास का जरिया बन रहा है अब आम बजट

आम बजट को जमीन पर साकार करने की प्रधानमंत्री की सीधी पहल। पेज 30-31

समाचार-सार
देश की प्रमुख खबरें | पेज 4-5

संगीत का बिस्मिल्लाह
कहानी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की | पेज 6

करोड़ों चेहरों पर आई मुस्कान
हैप्पीनेस डे पर जानिए केंद्र की योजनाओं की सफलता के आंकड़े | पेज 7

संघीय ढांचे की मजबूती, भारत के विकास के लिए अवसर
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक | पेज 26

भारत को विनिर्माण हब बनाने की दिशा में बढ़ते कदम
कैबिनेट के फैसले | पेज 27

पर्यावरण सुरक्षा पर प्रतिबद्ध भारत
अंतरराष्ट्रीय वन और जल दिवस पर विशेष | पेज 32-33

खुले स्कूल, खिलखिला उठे बच्चों के चेहरे
कोरोना के बाद अब सामान्य होती जिंदगी | पेज 34-35

टीकाकरण अभियान: अब चढ़ने लगा इंद्रधनुषी रंग
विषम परिस्थितियों में लक्ष्य पूरा कर रहा मिशन इंद्रधनुष | पेज 36-37

एक टीका भरोसे का
कोरोना से जंग में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू | पेज 38

प्रधानमंत्री का छात्रों को 'सेल्फ थ्री' का मंत्र
आईआईटी खड़गपुर और विश्व भारती में पीएम का संवाद | पेज 39

खेल-खेल में ज्ञान और संदेश
कहानी बदलते भारत की | पेज 40

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है। उसके बालमन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ता है जिसकी याद उसकी पूरी जिंदगी में ऊर्जा का संचार करती है। भारत में स्थानीय खिलौनों की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन इन खिलौनों पर विदेशी उत्पादों ने अपना अधिकार जमा लिया था। सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के बावजूद खिलौना निर्माण में भारत का हिस्सा महज 0.5 फीसदी है। ऐसे में अब इस परंपरा और खिलौना उद्योग को सहयोग देकर पुनर्जीवित करने के लिए सरकार बड़ा अभियान चला रही है।

सरकार का मकसद बच्चों को भारतीय संस्कृति-सभ्यता से परिचित कराने वाले खिलौना उद्योग को भरोसा देकर बच्चों को केमिकल मुक्त खिलौना देना है ताकि बच्चों के साथ-साथ देश की आर्थिक सेहत को भी मजबूती मिले। 'न्यू इंडिया समाचार' के इस अंक में बच्चों के चेहरों पर खुशी भरने वाली कहानियां और भारत को खिलौना उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर केंद्र सरकार के विशेष एक्शन प्लान को आवरण कथा बनाया गया है।

इतना ही नहीं, स्कूल-कॉलेज खुलने के बाद खिले छात्रों के चेहरे और विकास की सौगात से करोड़ों चेहरों की मुस्कान से सजा यह अंक दिल को सुकून देगा। लेकिन यह विराम नहीं, राष्ट्रीय भावना बन चुके आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत है।

हर बार की तरह आप अपना विचार और सुझाव हमें लिखते रहिए ...

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

जयदीप भटनागर

(जयदीप भटनागर)

आपकी बात...

न्यू इंडिया समाचार का अंक प्रदर्शित करता है - एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक सपना जो देखा गया है उसको साकार करते हुए प्रतीत होता है, ये अंक। इस अंक में उन सभी योजनाओं और भविष्य के रोडमैप को प्रकाशित किया गया है जो अपने आप में अद्भुत है।

अनिल धनगर
aashudhangar421@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का अंक वास्तव में विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी देने वाला है। 1-से 15फरवरी 2021 के अंक में लगने लगा उम्मीद का टीका, वैक्सीन से जुड़े सवाल-जवाब, एक देश एक व्यवस्था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और नवाचार-भारत, अब सेकेंड के अरबवें हिस्से को मापने में सक्षम, ज्ञानवर्धक, रोचक और संपूर्ण जानकारी युवाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।

यज्ञदत्त सारस्वत नागौर
yagyasar1958@gmail.com

केंद्रीय बजट 2021 पर आधारित न्यू इंडिया समाचार का ताजा अंक पढ़कर बहुत अच्छा लगा। 'सबका साथ सबका विकास' के मूलमंत्र वाले केन्द्रीय बजट के साथ ही इस अंक में सरकार की वैक्सीन मैत्री, केवडिया तक ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जैसी अनूठी पहल और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किये गये आम भारतीयों की बड़ी उपलब्धियों को इस अंक में शामिल करने से पत्रिका की शोभा और बढ़ गई।

चौधरी शक्ति सिंह shaktisinghadv@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार के माध्यम से हमें बजट के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना से प्रेरित कोविड वैक्सीन को अपने पड़ोसी देशों को मुहैया कराने, गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी, सम्मान निधि की जानकारी मिली, जो ज्ञानवर्धक है। आपसे आग्रह है इस पत्रिका को नियमित रुप से हमें प्रदान करते रहें।

umtiwari86@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार के माध्यम से हमें प्रेरणादायक, नई और कई अन्य जानकारियां प्राप्त हुई। आपका प्रयास सराहनीय है। उम्मीद है भविष्य में भी इसी तरह प्रयास करते रहेंगें। न्यू इंडिया समाचार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई।

आकाश गोला संम्भल
akashgumsani@gmail.com

न्यू इंडिया का ज्ञानवर्धक अंक पाकर अत्यंत आनंद हुआ। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उठाये जा रहे लिए कदम सराहनीय हैं।

हरिलाल दलवानी
hari@aryaindia.com

आपकी पत्रिका का अंक मिला। पढ़ कर अत्यंत खुशी मिली। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मे हो रहे कार्यों की जानकारी मिली। पद्म भूषण ओर पद्मश्री प्राप्त महानुभावों की जानकारी अत्यंत सुन्दर तरीके से प्रस्तुत की गयी। आशा है भविष्य में प्रकाशित अंक में और भी जानकारी मिलेगी।

ओमप्रकाश दवे
omdave58@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार के इस अंक में प्रकाशित केंद्रीय बजट एवं अन्य जानकारी बड़ी ही लाभप्रद है। उम्मीद है ऐसी जानकारी भविष्य में प्राप्त होती रहेगी।

राम शंकर पाण्डेय
dr.ramshankarpandey@gmail.com

इस पत्रिका में दिये गये कन्टेंट बहुत ही बेहतरीन हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मददगार साबित होंगी।

mamtamadheshiya85@gmail.com

अब डिजिटल कैलेंडर

भारत सरकार ने पहली बार डिजिटल कैलेंडर और डायरी एप लॉन्च किया है। जीओआई एप पर सभी सरकारी योजनाओं, कार्यक्रम, प्रकाशन के साथ आधिकारिक अवकाश और तिथियों की जानकारी भी मिल जाएगी।

इसे गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर डाउनलोड कर सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर लिंक
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

आईओएस लिंक
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब भारत में

दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब अहमदाबाद के मोटेरा में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृहमंत्री अमित शाह ने 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। 1,32000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में जाना जाएगा। 63 एकड़ में तैयार इस स्टेडियम पर कुल 800 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इसका डिजाइन पिलरलेस है, मतलब इसके निर्माण में खंभों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी वजह से स्टेडियम के किसी भी हिस्से में बैठकर दर्शक मैच का पूरा मजा ले सकते हैं। पुराने स्टेडियम की फ्लड लाइट टावर की जगह नए बने स्टेडियम में एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जिसकी परछाई नहीं रहती। इससे पहले आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सबसे बड़ा स्टेडियम था। यह स्टेडियम 233 एकड़ में बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में 20 अलग-अलग तरह के स्टेडियम होंगे जिनमें से एक मेजर ध्यान चंद के नाम पर हॉकी का स्टेडियम होगा। कॉम्प्लेक्स में लगभग 3,000 अपार्टमेंट बनेंगे जिनमें 12,500 खिलाड़ी रह पाएंगे।

योग दिवस की तैयारी शुरू, हर माह की पहली तारीख को सीखें योग

वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में लोगों ने इस आयोजन को भारत की संस्कृति और परंपरा के एक उत्सव के रूप में अपनाया है। योग के अभ्यास को बढावा देने और अपनी जीवन शैली में योग को अपनाने में मदद देने के लिए आयुष मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। 45 मिनट का सामान्य योग अभ्यास क्रम (Common Yoga Protocol) इसी दिशा में सबसे लोकप्रिय योग कार्यक्रमों में से एक है। आयुष मंत्रालय द्वारा बहुत ही आसान प्रशिक्षण सत्रों और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से इन्हें सिखाने की शुरुआत की गई है। इसके लिए हर महीने की पहली तारीख को सुबह 7 बजे से शुरु होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारण किया जा रहा है। यह 21 जून तक चलेगा।

अब भारतीय कंपनियां भी कर सकेंगी भू-स्थानिक डाटा का सर्वे और मैपिंग

केंद्र सरकार ने देश की मैपिंग व भू-स्थानिक नीतियों में परिवर्तन कर इन्हें सरल करने की घोषणा की है। दरअसल, किसी खास क्षेत्र में धरती की सतह पर मौजूद भौगोलिक स्थिति और संरचनाओं की जानकारी को भू-स्थानिक (जियो-स्पेशियल) डाटा कहते हैं। एक समय यह स्थिति थी कि भारत को इस डेटा के लिए विदेशी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब भारतीय कंपनियां बिना किसी इजाजत के सर्वे और मैपिंग कर सकती हैं। नई नीति के तहत सरकारी एजेंसियों जैसे भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के भू-स्थानिक डाटा को सार्वजनिक और निजी कंपनियों को मुहैया कराया जाएगा। इससे अब भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के मुकाबले खड़ी हो पाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2030 तक भू-स्थानिक डाटा का क्षेत्र करीब 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को भी फायदा होगा।

मंदी से बाहर निकली अर्थव्यवस्था, जीडीपी में वृद्धि दर अब पॉजिटिव

वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी से बाहर निकल आई है। इस दौरान जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जब लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था घटती है तो तकनीकी तौर पर उसे मंदी कहते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी -23.9% और दूसरी तिमाही में -7.5% घटी थी। न्यू इंडिया समाचार के 16 से 31 दिसंबर के अंक में दिए साक्षात्कार में मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमणियन ने तीसरे-चौथी तिमाही तक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के वापस पॉजिटिव आंकड़े पर आने की बात कही थी। तीसरे तिमाही के जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि में 3.9 फीसदी, मैन्युफैक्चरिंग में 1.6 फीसदी और निर्माण क्षेत्र में 6.2 फीसदी के बेहतर प्रदर्शन के कारण जीडीपी में वृद्धि संभव हो सकी है। साथ ही बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में 7.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल, जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाती है और इससे देश के आर्थिक विकास का पता चलता है।

ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पताल में भी करा सकेंगे अब इलाज

पीएमजय-आयुष्मान भारत के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाली केंद्र सरकार ने अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ईएसआईसी) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए शानदार पहल की है। इसके तहत ईएसआईसी के ऐसे लाभार्थी जिनके घर के 10 किमी के दायरे में ईएसआईसी अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं है, वो ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। उन्हें केवल ईएसआईसी के ई-पहचान पत्र और आधार कार्ड के साथ ओपीडी में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर द्वारा लिखी गईं ऐसी दवाएं जो लाभार्थियों को बाहर से खरीदनी पड़ेंगी, उनका भी नगद भुगतान ईएसआईसी डिस्पेंसरी से वापस मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होगी तो पूरा इलाज कैशलेस होगा।

ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाएगा ग्रीन एक्सप्रेस-वे

केंद्र सरकार सड़क पर सुरक्षा के साथ बेहतरीन सफर को आसान बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब दिल्ली से देहरादून के बीच 13 हजार करोड़ रु. की लागत से एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसके जरिए दिल्ली से देहरादून तक सड़क के रास्ते 6.5 घंटे में पूरा होने वाला सफर 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे के साथ दोनों शहरों के बीच बनने वाला यह ग्रीन एक्सप्रेस-वे 210 किमी का होगा। अभी दोनों शहरों के बीच की दूरी 235 किमी है। इस एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की न्यूनतम रफ्तार 100 किमी/घंटा होगी। हर 25-30 किमी पर सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। इस एक्सप्रेस-वे का रास्ता अभ्यारण्य से होकर गुजरता है, इसलिए वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए 12 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरीडोर बनाया जाएगा। दिल्ली से देहरादून तक 4 खंड में बनाया जा रहा यह एक्सप्रेस वे बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से होकर निकलेगा। इसके निर्माण कार्य में करीब 2 साल का वक्त लगेगा।

संगीत का बिस्मिल्लाह

कहते हैं कि शहनाई को अपनी बेगम और गंगा को मां कहने वाले बिस्मिल्लाह खान जब सुर की तान छेड़ते थे तो वक्त भी कुछ देर के लिए ठहर जाया करता था। उनके जाने के बाद बनारस की वो गलियां संगीत से जैसे हमेशा के लिए दूर हो गईं, जिन्हें कभी उनकी शहनाई की तान से सुबह और शाम का अहसास होता था

हिंदुस्तानियत से मोहब्बत इतनी कि दुनिया की कई जगहों से मिलने वाले देश छोड़ने के लालच ठुकरा दिए, तालीम ऐसी कि आज भी भारत की गंगा-जमुनी तहजीब में उनका जिक्र जरूर आता है, इज्जत इतनी कि लाल किले पर आजाद भारत के पहले तिरंगे के साथ उनकी शहनाई की स्वर लहरी भी गूंजी...उस्ताद बिस्मिल्लाह खान!

21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह यानी अमीरुद्दीन खान (कुछ लोग उनका नाम कमरुद्दीन खान भी बताते हैं, पर एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने अपना नाम अमीरुद्दीन खान बताया था) को यूं तो संगीत पिता से ही विरासत में मिला था। पिता राजा साहब के दरबार में संगीतकार थे। 6 साल की उम्र में अपने मामू अली बख्श 'विलायती' के यहां बनारस आए तो फिर ताउम्र के लिए बनारसी हो गए। मामा मंदिर में शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान ने उन्हीं से शहनाई बजानी सीखी। बिस्मिल्लाह खान कहते थे, 'पूरी दुनिया में चाहे जहां चले जाएं हमें सिर्फ हिंदुस्तान दिखाई देता है और यहां चाहे जिस शहर में हों, सिर्फ बनारस दिखता है।' कहा जाता है कि उस्ताद गंगा के पानी से वजू करते। पांच वक्त नमाज पढ़ते और शहनाई बजाने के पहले सरस्वती की उपासना करते। गंगा के लिए उनका प्यार ही था कि एक बार जब शिकागो यूनिवर्सिटी ने उन्हें शहनाई सिखाने के लिए आमंत्रित किया तो उनसे से कहा गया कि वो जहां रहेंगे वहां उन्हें बनारस जैसे पूरा माहौल बनाकर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाह खान ने तपाक से कहा- 'ये तो सब कर लोगे, ठीक है मियां! लेकिन मेरी गंगा कहां से लाओगे?' बाबा विश्वनाथ

जन्मः 21 मार्च, 1916 । निधनः 21 अगस्त, 2006

और उनकी सर्वव्यापकता पर खान साहब का अटूट विश्वास था। वे कहा करते थे, 'हर रोज बाबा के मंदिर के पट हमारी शहनाई की आवाज सुनने के बाद खुलते हैं, जीवन में इससे ज्यादा और क्या चाहिए?' उस्ताद ताउम्र भारत की गंगा-जमुनी तहजीब के वाहक बने रहे। आजाद भारत की पहली शाम पर लाल किले से प्रस्तुति देने वाले उस जमाने के वे इकलौते संगीतकार थे। उसके बाद लगभग हर साल, लाल किले से उनकी शहनाई की मधुर तान के साथ ही स्वाधीनता दिवस मनाने की परंपरा शुरु हो गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन की मंगल ध्वनि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ही बनाई हुई है। बॉलीबुड से भी बुलावा आया तो 'गूंज उठी शहनाई' से 'स्वदेश' तक कई फिल्मों में उनकी शहनाई की गूंज सुनाई दी।

1956 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्मभूषण, 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1992 में ईरान ने उन्हें तलार मौसिकुई पुरस्कार दिया। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। ●

इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे
20 मार्च

करोड़ों चेहरों पर आई मुस्कान

थीम-2021
दयालु हों
समझदार बने रहें।
शांत रहें।

खुश रहकर आप जिंदगी के मुश्किल पड़ाव को भी आसानी से पार कर लेते हैं। इसी के महत्व को जतलाने का दिन है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। वैसे तो खुशी बांटने और मनाने के लिए कोई एक दिन काफी नहीं, हर पल आप अपनी खुशी का जश्न मना सकते हैं। यह दिवस समावेशी, न्यायोचित और संतुलित आर्थिक विकास की महत्ता पर जोर देता है जिससे सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और सभी की खुशहाली व सुख को सुनिश्चित किया जा सके

जल जीवन मिशन

3.53 करोड़ ग्रामीण घरों में पहुंचाया नल कनेक्शन महज 17 महीनों में।

पीएम-उज्ज्वला

8.3 करोड़ महिलाओं यानी परिवारों को धुंआ मुक्त रसोई का उपहार।

जीवन ज्योति बीमा

जिंदगी की सुरक्षा परिवार को संबल, मात्र 330 रुपये सालाना पर 2 लाख रुपये के टर्म इंश्योरेंस के लिए 9 करोड़ 88 लाख लोगों करा चुके हैं पंजीकरण।

जन औषधि

700 जिलों में 6600 पीएम जन औषधि केंद्रों पर 1400 तरह की दवाई व 204 सर्जिकल उपकरण 90 % तक सस्ती दर में उपलब्ध।

उजाला योजना

36.71 करोड़ एलईडी लाइट वितरित की जा चुकी हैं। हर साल 18 हजार करोड़ से ज्यादा रु. की बचत।

आयुष्मान भारत

50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज से सेहतमंद जिंदगी का सफर।

पीएम आवास योजना

1,68,95,099

लोगों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अबअपना घर।

पीएम-स्वनिधि

2.071 करोड़ रु. का ऋण दिया गया। अब तक 2 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों को।

किसान का सम्मान-पीएम किसान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 11.64 करोड़ परिवारों के चेहरों पर सुकुन भरी मुस्कान। अब तक 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे गए।

उड़ान

1000 नए हवाई मार्गों को जोड़ने की शुरुआत। 53लाख लोगों ने 2500 रु. में किया हवाई सफर 3 साल में।

सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफार्म्स

अब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आम भारतीयों को भी अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका दिया है। वे सवाल पूछ रहे हैं। सूचनाएं ले रहे हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं। लेकिन, एक ओर यह उपयोगकर्ता को ताकत देता है तो गंभीर समस्या भी पैदा कर रहा है। इसलिए लंबे समय से सोशल मीडिया, समाचार पोर्टल और ओटीटी(ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म्स पर नियमन की मांग को अब केंद्र सरकार ने किया पूरा...

सरकार के पास कई शिकायतें आईं कि सोशल मीडिया पर मार्फ्ड तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग का मसला सिविल सोसायटी से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यहां तक कि संसद के दोनों सदनों में ओटीटी को लेकर लगभग 50 सवाल पूछे गए। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापार करने का स्वागत है। वे अच्छा कर रहे हैं। सरकार आलोचना और असहमति का स्वागत करती है। लेकिन यह बेहद जरूरी है कि यूजर्स को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाने के लिए फोरम दिया जाए। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को रेगुलेशंस की घोषणा करनी पड़ी। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिकस, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटटफॉर्म आएंगे।

भारत में सोशल मीडिया यूजर्स

- **53** करोड़ लोग व्हाट्सएप
- **1.75** करोड़ ट्विटर
- **44.8** करोड़ यूटयूब
- **41** करोड़ फेसबुक
- **21** करोड़ इंस्टाग्राम

क्या है नया नियम

- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित किया।
- ये नियम आम उपयोगकर्ताओं को उनके अधिकारों के उल्लंघन पर उनकी शिकायतों के समाधान और इनकी जवाबदेही तय करने के लिए सशक्त बनाती है।
- इसमें रचनात्मकता और अपने विचार व्यक्त करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करते हुए लोगों की विभिन्न चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी से जुड़े नियमों में आंतरिक एवं स्व-नियमन प्रणाली पर अधिक फोकस किया गया है।

मई तक लागू हो जाएगी नई गाइडलाइन

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा और इसके लिए कई स्तरों पर अधिकारियों को रखना होगा।
- नियमों का कितना पालन हुआ, इसकी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। रिपोर्ट में बताना होगा कि कितनी शिकायतें आई और कितने का निपटारा हुआ।
- सूचना का पहला स्त्रोत बताना होगा। खुराफात होने पर बताना होगा कि सबसे पहले इसे किसने शुरू किया। अगर देश के बाहर से शुरू हुआ तो बताना पड़ेगा कि भारत में इसे किसने शुरू किया।
- महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत मिलने के 24 घंटे भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम

- सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए भी कानून लेकर आएगी। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई बंधन नहीं था। समाचार पत्रों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नियम होता है और उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स है। फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड है।
- जो टीवी है उनके लिए प्रोग्राम कोड है और उनका सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में ओटीटी के लिए एक सुचारू व्यवस्था की गई है। इसके कंटेंट पर उम्र के मुताबिक क्लासिफिकेशन करना होगा और पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी।

- ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए तीन स्तर का तंत्र होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी और उन्हें एक शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा।
- नए नियम के आने पर ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को अपनी डिटेल बतानी पड़ेंगी जैसे कि वो कहां से काम करते हैं। इसके अलावा शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल बनाना होगा।

इसलिए थी नए दिशा-निर्देशों की जरूरत

- सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 11 दिसंबर, 2018 के आदेश में कहा था कि भारत सरकार सामग्री उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म और अन्य ऐप्लीकेशन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंगरेप की तस्वीरों, वीडियो तथा साइट को खत्म करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर, 2019 के आदेश में नए नियमों को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को समय-सीमा से अवगत कराने का निर्देश दिया था।
- राज्यसभा की तदर्थ समिति (एड-हॉक कमिटी) ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के चिंताजनक मुद्दे और बच्चों एवं समाज पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के बाद 03 फरवरी, 2020 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इस तरह के कंटेंट के पहले स्त्रोत की पहचान करने की सिफारिश की थी।
- इसके बाद मंत्रालय ने नियम का मसौदा तैयार किया और 24 दिसंबर, 2018 को लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। मंत्रालय को आम लोगों, सिविल सोसाइटी, उद्योग संघ और संगठनों से 171 सुझाव प्राप्त हुए।

विदेशी बाजार में छाने को तैयार

स्वदेशी खिलौना

बच्चों के हाथों में खिलौना सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होता, उसके शारीरिक और मानसिक विकास में भी इसका अहम योगदान होता है। खिलौनों में ही झलक मिलती है उस देश की परंपरा और संस्कृति की तो किसी कारीगर को इससे रोजगार भी मिलता है। ऐसे समय जब दुनियाभर में इनोवेटिव और मॉडर्न खिलौनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन 7 लाख करोड़ रुपये के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.5 फीसदी है। इसीलिए अब केंद्र सरकार ने भारत के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की शुरुआत की है ताकि वर्ष 2024 तक खिलौना निर्यात 2800 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर लाखों नए रोजगार पैदा किए जा सकें...

"मुझे खिलौना बनाने का शौक था। मैंने कोलकाता-राजस्थान जाकर प्रशिक्षण लिया, जब खिलौना बनाने लगे तो लोगों ने काफी पसंद किया। लोकल उत्पाद को बढ़ावा मिलता है तो उससे देखने वालों का नजरिया बदलता है।" यह कहना है झारखंड की रांची की रहने वालीं शोभा कुमारी का जिन्होंने खिलौने बनाने के अपने शौक को स्वरोजगार में बदल दिया। इसकी वजह- वोकल फॉर लोकल आह्वान और उनकी इच्छाशक्ति है। जब इस काम में अच्छी आमदनी होने लगी तो शोभा ने इस शौक में सलीना कच्छप, प्रतिभा टोपो जैसी अन्य महिलाओं को साथ जोड़ कर प्रशिक्षण दिया। हाथों में हुनर आने के बाद इन महिलाओं की अच्छी कमाई भी होने लगी है। हाथों के हुनर से शोभा आत्मनिर्भर बनीं तो देश के अलावा अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों में उनके बनाए स्वदेशी खिलौने से उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है।

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के सी.वी. राजू के गांव के ऐटिकोप्पका खिलौने बेहद प्रचलित थे। सौ साल पुरानी परंपरा वाले यह खिलौने लकड़ी से बनते थे। खास बात ये, कि ये खिलौने पूरी तरह गोल होते थे। जिससे बच्चों को चोट की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, ऊपर से लाख की सजावट, जिसमें कोई हानिकारक केमिकल का उपयोग भी नहीं होता था। लेकिन, धीरे-धीरे इन खिलौनों की परंपरा लुप्त हो गई। पेशे से किसान रह चुके राजू ने एक नई मुहिम छेड़ी और स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर बेहतरीन ऐटिकोप्पका खिलौना बनाकर इनकी खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है। इस खिलौने को अब जीआई टैग मिल चुका है। राजू के प्रयासों से न सिर्फ स्थानीय खिलौना परंपरा पुनर्जीवित हो गई है, बल्कि 150 से ज्यादा परिवार इस काम से जुड़कर आजीविका भी कमा रहे हैं।

"आत्मनिर्भर भारत आंदोलन में हमने फैसला किया है कि विदेश से जो उत्पाद आयात किए जा रहे हैं, उन्हें राजकोट में कैसे बनाया जा सकता है? लॉकडाउन में इस पर काफी काम किया। बहुत से खिलौने बनकर अब लांच हो चुके हैं।" यह कहना है गुजरात के राजकोट की खिलौना कंपनी अदिति टॉयज प्रा. लिमिटेड के जनरल मैनेजर हिमांशु वोरा का, जिन्होंने सौ फीसदी मेड इन इंडिया खिलौना बनाने की ठान ली है। यह कंपनी पिछले 5 साल से फूड पैकेट्स में मुफ्त दिए जाने वाले प्लास्टिक के छोटे खिलौने बनाती थी। लेकिन अब यहां बन रहे 160 तरह के अच्छे और बड़े खिलौने विदेशी बाजार के खिलौनों को टक्कर दे रहे हैं। वोरा अपने इन प्रयासों के बारे में बताते हैं, "कोरोना आपदा के बाद के दो महीने में हमने काम को बढ़ाया, नई तकनीक लाए और अब विदेशी उत्पाद को बंद करके पूरी तरह से भारतीय उत्पाद ही बना रहे हैं। अब हम बड़े, गेम्स और शैक्षणिक खिलौनों की दिशा में भी काम कर रहे हैं।" कंपनी ने इसके लिए 1 करोड़ 15 लाख रु. बैंक से कर्ज लेकर आपदा को अवसर में बदला। रिसर्च करके तीसरा प्लांट डाला और अब यहां रिमोट कंट्रोल कार से लेकर डॉक्टर सेट जैसे बड़े खिलौने बनाए जा रहे हैं।

इन कहानियों के भरोसे की बानगी तब देखने को मिली जब चंद महीने पहले दिल्ली में रहने वाले अभिनव बनर्जी अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को उपहार देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने झंडेवालान मार्केट गए। दिल्ली का यह मार्केट साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। लेकिन बनर्जी बताते हैं कि पहले वहां महंगे खिलौनों का मतलब विदेशी खिलौना होता था। लेकिन अब यहां के कई दुकानदार ग्राहकों को यह कहकर खिलौने बेच रहे हैं कि यह अच्छा वाला टॉय है क्योंकि यह भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। खिलौना उत्पादक ही नहीं, खरीददार भी भारत निर्मित खिलौनों की ही मांग करने लगे हैं। यही है सोच में परिवर्तन की कहानी। लेकिन यह कहानी एक साल में यूं ही नहीं बदल गई। इस परिवर्तन के पीछे खिलौनों की समृद्ध भारतीय विरासत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह आह्वान है जो जून और अगस्त 2020 को उन्होंने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था। वोकल फॉर लोकल के लिए जनमानस को झकझोरते हुए उन्होंने कहा था, "विश्व में खिलौना उद्योग लगभग सात लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। लेकिन जिस देश में इतनी बड़ी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, उस देश की इतनी कम हिस्सेदारी क्या अच्छी बात है? जी नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता हमें मिल कर इसे आगे बढ़ाना होगा।"

दरअसल कोरोना महामारी ने दुनिया को सकते में डाला तो भारत ने इस आपदा को ऐसे अवसर में बदला जहां कई हाथों के हुनर उभरे तो खिलौना उद्योग को हौंसला मिला। और अब उसी हुनर-हौसलों की ताकत से भारत दुनिया के खिलौना बाजार में छाने को तैयार है। इसकी वजह है 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र जो अब आंदोलन बन रहा है और खुदरा हो या थोक के व्यापारी, स्वदेशी खिलौनों की ही मांग करने लगे हैं। भारत की समृद्ध परंपरा वाले खिलौने- कठपुतली, कोंडापल्ली, कोप्पल, टेराकोटा, बीटल नट, कछुए के शेल से बने खिलौने, लकड़ी, बांस आदि से बनने वाले खिलौने एक बार फिर से मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और विदेशी के स्वदेशी विकल्प की कहानी लोगों को प्रेरणा दे रही है। कोरोना महामारी जैसी आपदा ने सिर्फ हाथों के हुनर को ही नहीं, भारत में काम कर रहे खिलौना क्षेत्र के उद्योगों को भी नया जीवन दिया है। बच्चों के खिलौने के बाजार पर विदेशी उत्पादों का कब्जा रहा है। लेकिन आपदा ने अवसर दिया तो अब गुजरात के राजकोट से लेकर कर्नाटक के चन्नापटना, कोप्पल, आंध्र प्रदेश के कोंडपल्ली-एटिकोप्पका, तमिलनाडु के तंजौर, असम के धुबरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जैसे टॉय कलस्टर ने मेड इन इंडिया खिलौना देने की ठान ली है। इस इच्छाशक्ति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किस तरह से सोच रही है इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि खिलौना क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के आधा दर्जन मंत्रालयों और दो विभागों का एक अलग समूह बनाया गया है जो रणनीतिक तरीके से खिलौनों की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित कर इस उद्योग को आत्मनिर्भरता की दिशा में लेकर बढ़ रहा है। यह भारतीय खिलौना उद्योग से जुड़े आत्मनिर्भर होने के उस संकल्प की शुरुआत भर थी, जिस दिशा में अब देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर इस शुरुआत की वजह क्या रही?

पीएम ने कहा- आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ अब समय है लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का

दिल्ली के लखमी चंद व कांगड़ा के विजय भी अब आत्मनिर्भरता की ओर

मेरे मां-बाप 43 साल से यह खिलौने बना रहे हैं। तभी से मैं भी इसे बनाता हूं। सरकार की ओर से इस क्षेत्र पर जिस तरह से ध्यान दिया गया है वह हाथ से खिलौने बनाने वाले मुझ जैसे लोगों के लिए वरदान बन गया है।" यह कहना है राजधानी दिल्ली के रघुबीर जेजे कॉलोनी में रहने वाले 55 वर्षीय लखमी चंद का। पिता से विरासत में मिली इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लखमी चंद बच्चों की हाथ से चलने वाली गाड़ी बना रहे हैं जिसे लोग टकटक भी कहते हैं। देखने में सहज और बच्चों को आकर्षित करने वाली टकटक गाड़ी को बनाना इतना आसान नहीं है। इससे जुड़ा सामान 40 बार हाथों से होकर गुजरता है तब जाकर ये गाड़ी तैयार होती है। कड़क पेपर पर पहियों के साथ घूमने वाली लकड़ी की आवाज सबका मन मोह लेती है। हाथों की कलाकारी अब दुनिया के सामने वर्चुअल रूप में सामने आई है।

कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के शाहपुर युवा ने इसे सही साबित किया है। उन्होंने 20 वर्षों से लुप्त हो रही बांस की कला को जीवंत किया है। बांस की कलाकृतियों से विजय खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, अन्य लोगों के भी स्वरोजगार का जरिया बन रहे हैं। विजय मेहरा का कहना है, "बांस आसानी से उपलब्ध है और कम लागत से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आज तक मैं 150 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं।"

हुनर और हौंसलों की वजह- समृद्ध प्राचीन सभ्यता

संसाधनों की कमी खिलौनों और खुशियों से दूर नहीं कर सकती। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही खिलौना हर परिवार का अहम हिस्सा रहा है। अमीर हो या गरीब, उपलब्ध संसाधनों और सामर्थ्य के हिसाब से अपने बच्चों को खिलौना देते रहे हैं। भारत में त्योहार हो या मेला, खिलौने प्राचीन संस्कृति की धरोहर के रूप में दिखते रहे हैं। दक्षिण में दशहरा के त्योहार के समय तो बाकायदा हर घर में अलग-अलग थीम पर लोग अपने घरों को खिलौनों से सजाते हैं, जिसे 'बोम्मला कोलुवु' कहा जाता है, जिसका अर्थ दिव्य उपस्थिति का अहसास होता है। इतना ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई में भी कई तरह के ऐसे खिलौने मिले हैं, जो उस काल में बच्चों के मानसिक विकास में अहम योगदान निभाते थे। देश की संस्कृति के साथ जीवन कौशल की झलक उस देश के खिलौनों में भी मिलती है। भारतीय खिलौना एसोसिएशन के तकनीकी समिति के संयोजक मनु गुप्ता का कहना है, "भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पारंपरिक खिलौने के 12 कलस्टर जीआई (GI) टैग वाले हैं, इसके अलावा भी 20 पारंपरिक टॉय कलस्टर हैं। पांच हजार साल पुरानी सभ्यता है भारतीय खिलौनों की। ऐसे में जरूरत है अब सभी को संगठित करने की।" विविधता में एकता का संदेश देने वाले भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्रों की स्थानीय कला उसके खिलौनों में भी झलकती है।

5 हजार साल पुराना भारतीय खिलौनों का इतिहास, फिर भी आज वैश्विक बाजार में हमारी स्थिति नगण्य ही है।

नौनिहालों के स्वास्थ्य का ख्याल...

वर्ष 2009-10 में गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में विदेशों से आयात होने वाले खिलौनों में थैलेटस नाम का जहरीला रसायन मिला है।

इस रिपोर्ट के अनुसार इस रसायन का इस्तेमाल बच्चों के खिलौनों में उपयोग होने वाली प्लास्टिक को मुलायम करने के लिए किया गया। लेकिन बच्चों, विशेषकर तीन से कम उम्र वालों के लिए यह बेहद खतरनाक है।

अमेरिका और यूरोप में तो यह प्रतिबंधित भी है। बच्चा जब इन खिलौनों को मुंह में डालता है तो थैलेटस की वजह से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, फेंफड़े खराब होना, हड्डियां कमजोर होने के साथ सांस की बीमारी हो सकती है।

इससे पहले 2007 में अमेरिका की दिग्गज निर्माण कंपनी मैटल इनकॉरपोरेटेड ने भी चीन में बने 8 लाख खिलौनों को वापस कर दिया था, क्योंकि इनमें जरूरत से ज्यादा लेड(सीसे) का इस्तेमाल किया गया था और बच्चों के लिए यह खिलौने खतरनाक थे।

इन दोनों खबरों को तब कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो तवज्जो मिली, लेकिन सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, वह नाकाफी ही रहे।

वर्ष 2019 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में मिलने वाले 121 तरह के खिलौनों का परीक्षण किया।

41.3%
सैंपल मेकेनिकल जांच में फेल

3.3%
सैंपल फैलाइट केमिकल जांच में फेल

12.4%
सैंपल मेकेनिकल और फैलाइट जांच में फेल

7.4%
सैंपल ज्वलनशीलता जांच में फ़ेल

2.5%
सैंपल मेकेनिकल जांच में फेल हो गए।

इन खिलौनों से बच्चे चोटिल हो सकते थे और यह त्वचा संबंधी रोगों का कारण भी बन सकता है।

यानी ये खिलौने स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। इस जांच में महज 33% खिलौने ही सही निकले।

बुलंद हौंसलों को नई उड़ान

अब खिलौनों की इसी समृद्ध परंपरा और भारतीय गौरव को एक मंच देने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है। भारतीय खिलौनों में नए-नए इनोवेशन के साथ संस्कृति को जोड़ते हुए खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर होते हुए कैसे दुनिया में आगे बढ़े, इसके लिए पहले महीने भर का टॉयकाथॉन का आयोजन किया गया और अब 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश के इतिहास का पहला 'खिलौना मेला' आयोजित किया गया। इस मेले की सफलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कानपुर का खिलौना उद्योग हो या राजस्थान के राजसमंद में मिट्टी के खिलौने बनाने वाले राजेंद्र कुम्हार या फिर इस्तेमाल हो चुके सामानों को रिसाइकिल कर उस पर चमड़े का प्रयोग करके नया रंग देने वाले इंदौर के खिलौना

विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी

85%
खिलौने विश्व में चीन से जाते हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन के देश हैं।

₹7 लाख करोड़
का है विश्व खिलौना बाजार। जिसके 2025 तक करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा तक पहुंच जाने की संभावना है।

0.5%
से भी कम है विश्व के खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी। यानी करीब 45 करोड़ रुपये

- भारत में एक साल में 3500 से 4500 करोड़ रुपये के खिलौने बेचे जाते हैं, जिसमें से 15 फ़ीसदी ही स्वदेशी हैं, यहां भी 85 फीसदी खिलौने दूसरे देशों से आयात होते हैं।
- दुनिया में खिलौना बनाने में जो कंपनियां सबसे आगे है, उनमें लेगो, मेटल और बान्दाई नामको एंटरटेनमेंट जैसे नाम शामिल है। इनमें से कई के प्लांट चीन में हैं।
- विश्व बाजार के 5% प्रतिवर्ष तो भारतीय बाजार के 10% से 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने की संभावना है। ऐसे समय जब हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो खिलौनों के 7 लाख करोड़ रुपये के वैश्विक बाजार में भारत की मात्र 0.5 फीसदी की हिस्सेदारी बेहद कम हो जाती है।

केंद्र सरकार ने इस विश्व बाजार में वर्ष 2024 तक कम से कम 2800 करोड़ रुपये तक की हिस्सेदारी का लक्ष्य तय किया है।

निर्माता जीतेंद्र या फिर छात्र और शिक्षक, सबको यह उम्मीद जगी है कि लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकल चीजों को मुख्यधारा में लाने का अनोखा प्रयास हो रहा है। राजेंद्र कुम्हार की उम्मीद उनके इस भरोसे में दिखती है, "आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के तहत हुए इस आयोजन से मिट्टी के खिलौने बनाने वाले स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। भारत के लिए यह बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमें विदेशी खिलौनों से मुकाबला करना है और अपनी संस्कृति को बचाना है।" मेले के प्रति उद्यमियों और कारीगरों के रुझान को देखते हुए इसे 2 दिन और बढ़ाना पड़ा।

सेहतमंद बचपन के लिए जरूरी स्वदेशी खिलौना

खिलौने बच्चों को खूब लुभाते हैं, खेल-खेल में उन्हें कितना कुछ सिखाते हैं। सभी इससे वाकिफ हैं। लेकिन विडंबना ही है कि भारत का विस्तृत समृद्ध, व्यापक खिलौना उद्योग वक्त के साथ विदेशी खिलौनों की भीड़ में कहीं खो सा गया है। ऐसे में सिर्फ खिलौनों की भारतीय संस्कृति को

क्लस्टर के जरिए परंपरा को जीवित रखने की मुहिम

उत्तर प्रदेश

वाराणसी पारंपरिक खिलौनों के लिए प्रसिद्ध। सहारनपुर और ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के खिलौने बनाने की तैयारी।

वाराणसी | सहारनपुर | ग्रेटर नोएडा

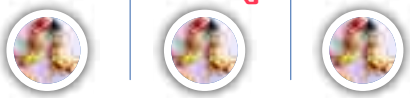

आंध्र प्रदेश

एटिकोप्पका और कोंडापल्ली में लकड़ी से बनाए खिलौनों में मिलती है ग्रामीण भारत की झलक।

एटिकोप्पका | कोंडपल्ली | कडपा

बिहार

सिक्की घास से बनाए खिलौने खास पहचान रखते हैं।

दरभंगा | सिक्की

लद्दाख

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टॉय क्लस्टर से स्थानीय खिलौनों को वैश्विक पहचान देने की तैयारी।

लद्दाख

हिमाचल प्रदेश

अब तक पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के खिलौने अब पूरी दुनिया में निर्यात होंगे।

शिमला

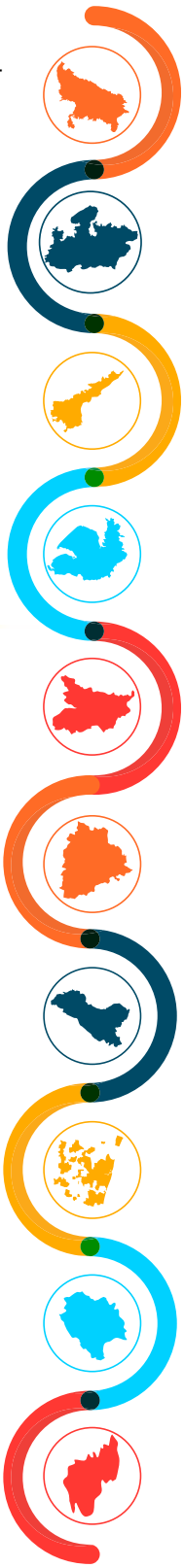

मध्य प्रदेश

इंदौर में 1000 एकड़ जमीन चिह्नित, बुदनी को भोपाल के करीब होने का लाभ मिलेगा।

इंदौर | भोपाल | बुदनी

गुजरात

व्यापार के मामले में समृद्ध गुजरात अब खिलौना निर्माण का हब बनने को तैयार।

पाटण | सागरपुर

तेलंगाना

लकड़ी से बनने वाले पशु-पक्षियों के खिलौने निर्मल खिलौनों के नाम से ही प्रसिद्ध हैं।

निर्मल

पुडुचेरी

फ्रेंच वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध पुडुचेरी अपने चिकनी मिट्टी के खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है।

पुडुचेरी

त्रिपुरा

बांस की कारीगरी वाले खिलौने यहां की विशेषता हैं।

अगरतला

राजस्थान

लाख के खिलौने और राजस्थानी कठपुतली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अब इनके निर्माण पर विशेष फोकस।

चित्तौड़गढ़ | उदयपुर | कठपुतली नगर

झारखंड

लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों के साथ हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध।

धनबाद

केरल

केरल की व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध एर्नाकुलम में खिलौना निर्माण हब बनने की संभावना

एर्नाकुलम

सिक्किम

सिक्किम में हाथों के जरिए सॉफ्ट टॉय बनाने का काम 60 साल से ज्यादा पुराना है।

असम

टेडी बीयर निर्माण का हब है। टॉय क्लस्टर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बनेगी।

नागालैंड

सांस्कृतिक रूप से संपन्न नागालैंड अब खिलौना निर्माण में नई कहानी लिखने का तैयार।

नागालैंड

कर्नाटक

खिलौनों के लिए विश्व प्रसिद्ध चन्नपटना भारत का पहला टॉय क्लस्टर है।

चन्नपटना | किन्हल

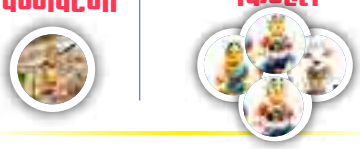

ओडिशा

ब्रास और मेटल के हस्तशिल्प के लिए मयूरभंज प्रसिद्ध है, खिलौना निर्माण की नई पहल की तैयारी।

मयूरभंज

महाराष्ट्र

सावंतवाडी

सिंधुदुर्ग के सावंतवाडी में बने लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। टॉय क्लस्टर के जरिए नए रोजगार मिलने की संभावना।

तमिलनाडु

तंजौर

सिर हिलाने वाली गुड़ियों के तौर पर प्रसिद्ध तंजौर डॉल्स का नाम हर कोई जानता है।

केंद्र सरकार की पहल...

- औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में खिलौना उत्पादन से जुड़ी करीब 4000 सूक्ष्म-लघु इकाईयां काम कर रही हैं। इनमें 75 फीसदी सूक्ष्म, 22 फीसदी लघु व मध्यम और 3 प्रतिशत बड़ी इकाईयां हैं।
- केंद्र सरकार दो तरफा पहल कर रही है। पहला, स्थानीय खिलौना उद्योग को बेहतर बनाने की और दूसरा, उन्हें उचित बाजार मिले इसके लिए भारतीय बाजार में मौजूद विदेशी खिलौनों से प्रतियोगिता का माहौल देने की।
- इसके लिए जनवरी-फरवरी में पहली बार देश में टॉयकाथॉन की शुरुआत की गई। इसके बाद 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश के पहले टॉय फेयर का आयोजन किया गया है।
- भारत में मिलने वाले खिलौने बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर हों इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) का सर्टिफिकेशन अनिवार्य किया गया। भारत में बनने वाले हस्तशिल्प और जीआई खिलौनों को इसकी छूट रहेगी।
- भारतीय बाजार में मिलने वाले विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है, ताकि भारतीय खिलौना उद्योग को सहारा मिल सके। भारतीय खिलौना उद्योग को 100 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है।

पुनर्जीवित करना ही नहीं, हमारे-आपके बच्चों के स्वस्थ बचपन के लिए स्वदेशी खिलौना जरूरी है। भारतीय बाजार में विदेशी खिलौनों की बढ़ती भीड़ देश की आर्थिक सेहत ही नहीं, हमारे-आपके नौनिहालों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद तैयार हुई भारतीय गुणवत्ता परिषद की एक रिपोर्ट बताती है कि विदेशों से आयातित करीब 67 फीसदी खिलौने गुणवत्ता परीक्षण में फेल रहे हैं। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आयातित खिलौनों में लेड, आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल होते हैं। ऐसे में भारतीय संस्कृति के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति भारत की गंभीरता को देखते हुए स्वदेशी खिलौने जरूरी हैं।

वैश्विक बाजार में धमक की तैयारी

दुनिया में खिलौनों का बाजार करीब 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी महज 0.5 फीसदी ही है। जबकि 2025 तक खिलौनों का वैश्विक बाजार 9 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। अभी भी भारत में 85 फीसदी खिलौने विदेश से आयातित होते हैं और स्थानीय भागीदारी 15 फीसदी है। जबकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी के मामले में दुनिया की एक तिहाई आबादी भारत में रहती है। ऐसे में भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों है। वैश्विक खिलौना व्यापार में आने वाले वर्षों में भारत सरकार की सहायता से भारतीय उद्यमी और कुशल कारीगर 2800 करोड़ रुपये के खिलौनों का व्यापार करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए खिलौना उद्योग में आत्मनिर्भरता के साथ लोकल के लिए वोकल होने के मंत्र से यह क्षेत्र नई उड़ान भरने को तैयार है।

सरकार का फोकस इन 9 तरह के खिलौनों पर

ऐसे खिलौने जिनमें भारत के इतिहास और संस्कृति की झलक मिलती हो।

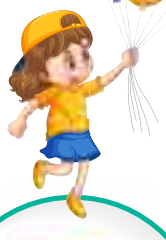

कॅरियर से संबंधित खिलौने

बच्चों को शिक्षा देते हों और उन्हें सिखाने में मदद कर सकते हों।

जिनसे सामाजिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा मिलती हो।

पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों।

फिटनेस और खेलों से संबंधित खिलौने।

पुराने और पारंपरिक भारतीय खिलौनों का नए तरीके और सोच के साथ निर्माण।

दिव्यांग बच्चों के उपयोग के लिए।

ऐसे खिलौने जो बच्चों की तर्क शक्ति बढ़ाएं और उनमें नई तरह से सोचने की शक्ति विकसित हो।

देश के पहला खिलौना मेला और टॉयकाथॉन

वह देखो मां आज खिलौने वाला फिर से आया है कई तरह के सुंदर-सुंदर नए खिलौने लाया है हरा-हरा तोता पिंजड़े में, गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सर-सरसर चलने वाली।

सीटी भी है कई तरह की... कई तरह के सुंदर खेल... चाभी भर देने से भक-भक करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी... पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी-सेट है... छोटे-छोटे हैं लोटा-थाली।

खेला है भाई खेला है, बड़ा रंग-बिरंगा खेला है। फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है खेला है बैटरी से चलता रोबो सरपट जाए दौड़ा.. लट्टू घुमा के है सट्ट से कहीं छोड़ा

इनोवेशन और रिसर्च के साथ पारंपरिक भारतीय खिलौनों के नए तरीके से निर्माण की तैयारी

खेल-खेल में सब समझा दे, मैथ-साइंस-भूगोल सिखा दे.. ले के आया ऐसे खिलौने मेला ये अलबेला।

एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है। भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है, मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान भी होता है।

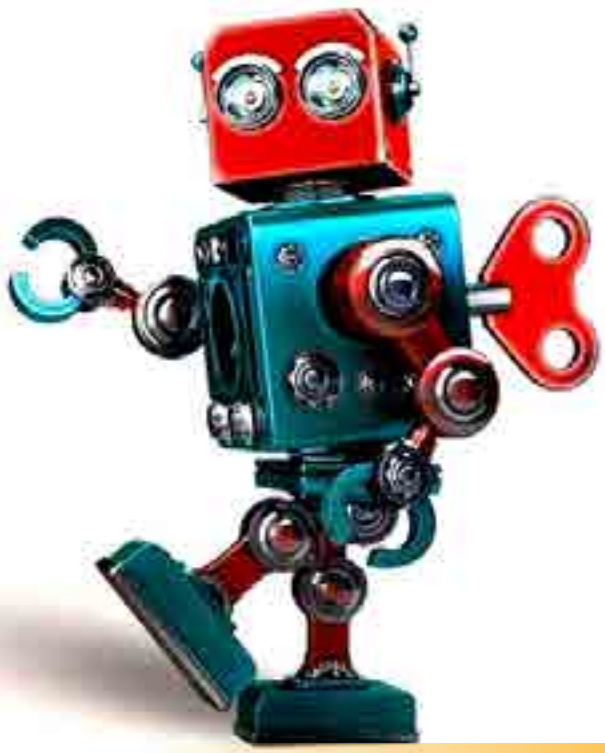

ऐसे गीत अगर फिर आपके कानों में गूंजने लगे तो अचरज मत करिएगा क्योंकि यह भारतीय खिलौनों की समृद्ध परंपरा की आवाज है जिसे आपने कविताओं-कहानियों और फिल्मों में खूब देखा-सुना होगा। भारतीय परंपराओं की सजीव तस्वीर प्रस्तुत करने वाले खिलौनों से जुड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने और खिलौनों की दुनिया के सतरंगी रंगों को धरातल की वास्तविकताओं से जोड़ने के लिए पहली बार किसी केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी पहल की है। भारतीय खिलौना उद्योग को लोकल से वोकल करने और आत्मनिर्भर भारत के जरिए वैश्विक खिलौना बाजार में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने की सोच को आगे बढ़ाते हुए ही देश के पहले टॉय मेला का आयोजन 27 फरवरी से 4 मार्च तक किया गया। इसमें 1200 से ज्यादा एक्जीबिटर ने हिस्सा लिया। इससे पहले सरकार ने 5 जनवरी को टॉयकाथॉन की शुरुआत की थी जो 25 फरवरी तक चला। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन-2021 को लॉन्च किया। इस विशेष प्रकार के हैकाथॉन में 12 लाख से अधिक युवाओं, शिक्षकों और विशेषज्ञों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 7,000 से अधिक नए-नए आइडिया मिले।

इसके बाद पहली बार भारत सरकार लाई- बच्चों के फन और लर्निंग की जरूरतों को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला। इस खिलौने मेले में फन, साइंस, मॉडर्न, लोकल, एजुकेशनल और इलेक्ट्रोनिक टॉयज की भरपूर वैराइटी भारत में ही बने और विदेशों में जाए, इसके लिए विशेषज्ञों से यह जानने का प्रयास हुआ कि किस तरह के खिलौने आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास में योगदान दे सकते हैं। खेल-खेल में सीखने की धारणा को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, वेबिनार, हुए। इसमें ग्लोबल निवेशक, एमएसएमई, निर्यातक, लोकल इंडस्ट्री का महाकुंभ हुआ। इसमें देश-दुनिया के 25 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया और भारत की 1 हजार से ज्यादा कंपनियों और कुशल कारीगरों ने विरासत में मिले अपने अनूठे हुनर का प्रदर्शन दुनिया के सामने किया।

मंथन से निकला कैसा होगा खिलौना

खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, वहां बचपन की

डिजिटल गेमिंग पर भी भारत की नजर

आपको याद होगा एक बार 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में एक मां ने अपने बेटे की ऑनलाइन गेम की लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया तो उन्होंने पूछा था- पबजी वाला है क्या? लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा- " ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम बच्चों को तकनीक से दूर नहीं रख सकते। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि बच्चे प्ले-स्टेशन से प्ले-फील्ड की ओर जाएं।"

भारत में डिजिटल गेमिंग के बाजार और बच्चों में इसकी लत को समझाने का यह सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन यह विडंबना है कि भारत में अभी खेले जाने वाले 98-99 फीसदी ऑनलाइन और वर्चुअल रियलिटी गेम दूसरे देशों के हैं। कोरोना काल में डिजिटल गेमिंग का बाजार भी बढ़ा है। ऐसे में भारतीय खिलौना उद्योग के साथ केंद्र सरकार डिजिटल गेमिंग के सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व बाजार में उपस्थिति के लिए काम कर रही है। फरवरी 2020 में इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक कमेटी बनाई गई थी। विशेषज्ञों की इस कमेटी में डॉ. पराग मनकीकर, डॉ. उन्नत पंडित, पंकज सप्कल, डॉ. आरती प्रकाश और अवि दास शामिल थे।

कमेटी के सदस्य डॉ. पराग कहते हैं- "ऐसे नए डिजिटल गेम्स से भारत के इतिहास और संस्कृति को जानने का मौका मिलगा और अभी कैंडी क्रश सागा जैसे जो तमाम गेम हैं उनके मुकाबले वैश्विक बाजार में हम खुद को स्थापित कर पाएंगे।" वहीं केंद्र सरकार की पहल को वक्त की जरूरत बताने के साथ डॉ. उन्नत पंडित इस दिशा में और तेजी के साथ काम करने की जरूरत बताते हुए कहते हैं- "तमाम सेक्टर्स में हम जिस तरह से इनोवेशन के रास्ते आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, डिजिटल गेमिंग के सेक्टर्स में भी हमें इस पर ध्यान देना होगा।"

क्यों है जरूरत...

एक नजर भारत में ऑनलाइन गेम के बाजार पर

26.36 करोड़ कुल उपयोगकर्ता

81.78 करोड़ रुपये कुल कमाई

सरकार का ध्यान इन 3 बातों पर ...

- **पौराणिक कथाओं पर आधारित गेम:** विश्व में जो डिजिटल गेम खेले जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर मारधाड़, मनोरंजन से जुड़े हैं। इनसे कुछ सीखने के बजाय बच्चे इनके आदि हो जाते हैं। भारत जैसे देश में पंचतंत्र और पौराणिक कथाओं का लंबा इतिहास है, अगर गेम इन पर आधारित हों तो बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा।
- **नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर आधारित:** भारत जैसा देश अपने भीतर सभ्यता और संस्कृति का एक अध्याय समेटे हुए है। इसलिए बेहतर होगा कि बच्चों के लिए ऐसे डिजिटल गेम की शुरुआत की जाए, जिनके जरिए उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। अमेरिका और यूरोप में ऐसे गेम की शुरुआत हो चुकी है। यहां के 500 से ज्यादा स्कूलों में एक डिजिटल गेम से जुड़े हुए असाइनमेंट बच्चों को दिए जाते हैं। यह एक जीवन कौशल सिखाने वाला डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इससे बच्चों को कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलता है।
- **वर्चुअल रियलिटी गेम:** वर्चुअल रियलिटी गेम के पात्र के रूप में अगर विवेकानंद, वीर सावरकर या शिवाजी हों और असली जीवन में उनके द्वारा किए गए काम इस गेम में टास्क के रूप में हों तो बच्चे इनके बारे में तो जानेंगे ही, उनके अच्छा सीखने को भी मिलेगा।

ऐसे होगी शुरुआत...

- भारत में गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की कौशल क्षमताओं में बढ़ावा देने पर जोर।
- डिजिटल और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ इनकी शुरुआती स्तर पर देखभाल(इन्क्यूबेशन) व जरूरी सहायता मुहैया कराने पर ध्यान।
- डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश। डिजिटल गेमिंग, विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन और कॉमिक्स के लिए एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है। इसके लिए आईआईटी बॉम्बे और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने करार किया है।

7 दशक तक उपेक्षा का शिकार रहा हमारा खिलौना, आइए इसे आत्मनिर्भर बनाएं

27 फरवरी से शुरु हुए देश के पहले टॉय फेयर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों के साथ उनसे जुड़ी लंबी सांस्कृतिक पहचान का जिक्र करते हुए स्थानीय खिलौना उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। पढ़िए उनके संबोधन के अंश...

- ये पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है।
- खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले 'चतुरंग या चादुरंगा' के रूप में भारत में खेला जाता था।
- मैं देश के खिलौना बनाने वालों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण और मानसिक विकास के लिए बेहतर हों। ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हों।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमान पर शामिल किया गया है। जिससे बच्चों की तार्किक क्षमता में बढ़ोतरी हो सके।
- खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास परंपरा भी है और तकनीक भी है, भारत के पास अवधारणा भी हैं, और उस पर अमल करने की प्रतिभा भी। हम दुनिया को इको-फ्रेंडली खिलौनों की ओर वापस लेकर जा सकते हैं।
- पिछले 7 दशकों में भारतीय कारीगरों की, भारतीय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम ये है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं।

- भारतीय बच्चे अपने देश के वीरों, हमारे नायकों से ज्यादा बाहर के स्टार्स के बारे में बात करने लगे। इस बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूत चेन भी तोड़ के रख दी है।
- इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले वर्ष से खिलौनों के क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। आयात होने वाले खिलौनों की हर खेप में भी टेस्टिंग की इजाजत दी गई है।
- खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्जा दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग प्रतिस्पर्धी बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बनें, और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं।

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, मन भी बनाते हैं और मकसद भी गढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों को लेकर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों को साझा किया था, वही विचार भारतीय खिलौनों का आधार बन रहा है। उनके मुताबिक, खिलौनों के बारे में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेहतर खिलौना वो होता है जो संपूर्ण नहीं हो ताकि बच्चे खेल-खेल में उसे पूरा करें। जबकि सुंदर विदेशी खिलौनों में सीखने या बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए, गुरुदेव कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के बचपन को बाहर लाये, उसकी रचनात्मकता को सामने लाए। खिलौना ऐसा हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। भारत में ऐसे खिलौने बनाए जाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हों। बच्चों के जीवन के अलग-अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इसको पहली बार भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जोड़ा गया है। खेल-खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां जाना, इन सबको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यानी पाठ्यक्रम की खिचड़ी में खिलौनों का तड़का लगाया गया है ताकि सोमवार हो या रविवार इंडिया खेले सपरिवार। बच्चे अपने खुद के खिलौने

पचीसी या चौपड़

भारत में खेल पीढ़ी दर पीढ़ी और सांस्कृतिक माध्यमों के द्वारा न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि मानसिक क्षमताओं के विकास और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए भी खेले जाते रहे हैं। ऐसे ही मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए प्राचीन समय में 'पचीसी' और 'चौपड़' खेलों को खेला जाता था। यह खेल तमिलनाडु में "पल्लान्गुली", कर्नाटक में 'अलि गुलि मणे' और आन्ध्र प्रदेश में "वामन गुंटलू" के नाम से खेला जाता है। कहा जाता है कि यह ,खेल दक्षिण भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया और फिर दुनिया में फैला।

आंध्र प्रदेश के ऐटिकोप्पका खिलौने

*आंध्र प्रदेश का एटिकोप्पका लाख से मढ़े हुए लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इन खिलौनों को बनाने की शुरुआत करीब 400 साल पहले हुई। इस कला को लक्कपिडातालू नाम से जाना जाता है। इन्हें खिलौनों को बनाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत के साथ ही इन्हें दुनियाभर में निर्यात किया जाता है। आंध्र प्रदेश और ऐटिकोप्पका के लिए ये गर्व की बात है कि इन खिलौनों को वर्ष 2017 में जीआई टैग(**GI**) मिला हुआ है ।*

बनाएं और छा जाएं यह सोच अब बचपन से ही साकार करने की दिशा में सरकार ने अनूठी पहल की है।

आधुनिकता और परंपरा का समावेश

ऐसे में प्राचीन कहानियों को अब एनिमेशन के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने और पुरानी परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रूचि पैदा करने की पहल शुरु हो चुकी है। विदेशी खिलौनों में आकर्षण होता है, लेकिन उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। जबकि पुराने ग्रंथों को भारतीय खिलौनों के जरिए बालमन में समेटा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- "हमारे देश में पारम्परिक खेलों की बहुत समृद्ध विरासत रही है। जैसे, आपने एक खेल का नाम सुना होगा – पचीसी। यह खेल तमिलनाडु में "पल्लान्गुली", कर्नाटक में 'अलि गुलि मणे' और आन्ध्र प्रदेश में "वामन गुंटलू" के नाम से खेला जाता है। आज हर बच्चा सांप-सीढ़ी के खेल के बारे में जानता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतीय पारंपरिक खेल का ही रूप है, जिसे 'मोक्ष पाटम या परमपदम' कहा जाता है। मेरा, घर के नाना-नानी, दादा-दादी, घर के बुजुर्गों से आग्रह है, कि, नयी पीढ़ी में ये खेल

15 मंत्रालयों ओर विभागों को शामिल कर पहली बार नेशनल टॉय एक्शन प्लान तैयार किया गया।

आप अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कौन करेगा! जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है, तो बैलेंस बनाने के लिए, ऑनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी, हमें, ऐसा करना ही होगा। हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हमारे स्टार्टअप के लिए भी यहां एक नया अवसर है, और, मजबूत अवसर है।" अब केंद्र सरकार की पहल से प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर नया रूप दिया जा रहा है। राजस्थान-गुजरात की मशहूर कठपुतली के

बंगाल के कृष्णा नगर के मिट्टी के खिलौने

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का कृष्णा नगर अपने मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। यहां मिट्टी से बनाई जाने वाली गुड़िया और दूसरे खिलौने अपने उत्कृष्ट आकार और आकर्षक डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। इन खिलौनों को बनाने के लिए यहां की 'घुरनी' नदी के किनारे मिलने वाली खास प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। विश्व के सभी खिलौना संग्रहालयों में आपको कृष्णानगर के मिट्टी से बने खिलौने जरूर मिलेंगे।

बनारस के लकड़ी के खिलौने

बनारस की काष्ठ-कला (लकड़ी से बनी मूर्तियां) पूरी दुनिया में मशहूर है। इस काष्ठ कला ने दुनिया में बनारस को एक अलग पहचान दी है. जीआई (जियोग्राफिकल इंडीकेशन) टैग मिलने के बाद बनारस का लकड़ी कारोबार कई गुना बढ़ गया है। शहर के कश्मीरीगंज, खोजवां इलाके में बड़े स्तर पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। यह आइटम विदेशों में खूब पसंद किए जाते हैं।

आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर सूचना व प्रसारण मंत्रालय गेमिंग, वीएफएक्स, एमिनेशन जैसे कोर्स के लिए सेंटर शुरू करेगा।

जरिए धार्मिक कथाओं से बच्चों को रू-ब-रू कराने की पहल हो रही है तो एनिमेशन के जरिए भारतीय संस्कृति से बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है।

सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए पहल

भारत में भारतीय खिलौने बनें, लाखों लोगों को काम मिले, पूरी शिक्षा प्रणाली में भारतीय खिलौनों का क्या स्थान हो सकता है। बच्चे जब अपनी उम्र में अलग-अलग कौशल का विकास करते हैं उसमें खिलौनों का प्रमुख योगदान रहता है। लेकिन कोरोना के कालखंड में जब देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था और बच्चों को भी घरों में बंद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखे तरह के प्रयोग पर बनी गांधीनगर की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा, एमएसएमई के साथ मिलकर मंथन और चिंतन किया कि बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। इसी से भारत को खिलौना उत्पादन में दुनिया का हब बनाने का विचार निकला। भारत में खिलौनों के कई कलस्टर विकसित हो रहे हैं क्योंकि भारत में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है। ऐसे में जिस देश के पास इतनी बड़ी विरासत, विविधता और युवा आबादी हो वहां खिलौना बाजार में भारतीय हिस्सेदारी नगण्य होना चिंता की बात थी। जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व के स्तर से लोकल फॉर वोकल और खिलौना उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया गया और नीतिगत सुधारों के साथ शुरू हो गया खिलौना उद्योग को आत्मनिर्भर बना स्थानीय कला-संस्कृति को समृद्ध बनाने का नया आंदोलन। ठीक उसी तरह जिस तरह महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के जरिए देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का

चन्नपटना के 300 साल पुराने खिलौने

चन्नपटना खिलौनों का इतिहास 300 साल पुराना है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के शासन काल में लाख का बना ये खिलौना बच्चों का दिल बहला रहा था। तब से अब तक इस कला ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। इसे बनाने वाले शुरुआती कारीगर बैंगलुरू के करीब चन्नपटना में बस गए जिसके बाद से इन खिलौनों का नाम चन्नपटना खिलौना पड़ गया।

तंजौर डॉल्स यानी सिर हिलाती गुड़िया

तंजौर या तंजावुर खिलौनों के बारे में कई तमिल साहित्य में जानकारी मिलती है। आपने भी कई जगह, या फिल्मों में ये डॉल देखी होंगी, जिनका सिर और शरीर ऐसे हिलता है जैसे की ये नाच रही हैं। इसलिए इन्हें तंजौर की डॉन्सिंग डॉल्स भी कहा जाता है। इन डॉल्स की न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कई देशों में मांग है।

भारत में खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ पहली बार टॉय टूरिज्म की संभावनाओं की तलाश

अहसास कराने का प्रयास किया था।

इसकी बानगी कोरोना काल में ही दिखने लगी जब रांची के रहने वाले मनोज कुमार ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। जब बाहर से कोई खिलौना नहीं आ रहा था तो उन्होंने खिलौना निर्माण का काम शुरू किया। मनोज कहते हैं, "यही मौका था जब बाहर से कोई खिलौना नहीं आ रहा था तो मैंने टेडी बीयर बनाने की शुरुआत की और कुछ कारीगरों को रोजगार दिया। युवाओं की सोच में लोकल फॉर वोकल से बड़ा बदलाव आया है क्योंकि आज युवा रोजगार देने वाला बनना चाहते हैं। युवा उद्यमियों के आने से कई लोगों को अवसर मिले हैं।" 'द इंडियन टॉयज फेयर- 2021' और टॉयकाथॉन का नतीजा है कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस दौर में देश में ही बने कंप्यूटर गेम्स का ट्रेंड बढ़ा है। स्टार्टअप हो या उद्यमी या फिर छात्र-शिक्षक, विशेषज्ञ सभी देश को खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि असहयोग आंदोलन से बोया गया बीज आत्मनिर्भर भारत के वट वृक्ष के रुप में परिवर्तित हो सके। 'आइए मिलकर खिलौने बनाएं। टीम अप फॉर टॉयज' जैसी केंद्र सरकार की मुहिम का ही नतीजा है कि भारतीय खिलौना उद्योग नई पहचान, नई उड़ान के साथ ग्लोबल खिलौना बाजार में अपना नया मुकाम बनाने को तैयार है। निश्चित तौर से इस अनूठी पहल से यह गीत गुनगुना सकते हैं, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना क्योंकि बुलंद हौंसलों को समेटे भारत अब आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ा रहा है। ●

संघीय ढांचे की मजबूती, भारत के विकास के लिए अवसर

भारत ने कोरोना काल में संघीय ढांचे की मजबूती का प्रदर्शन करते हुए इस वैश्विक महामारी से सफल जंग लड़ी, जिसे कायम रखते हुए देश विकास की ओर निरंतर कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 20 फरवरी को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य व पोषण जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने देश के विकास की दिशा का खास तौर से जिक्र किया, जिसमें जन-धन खाते, टीकाकरण, उज्ज्वला, शौचालाय और पक्के मकान जैसी उपलब्धियों से गरीबों के सशक्तीकरण, जल जीवन मिशन से कुपोषण पर प्रहार और गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम के तहत हो रहे काम शामिल हैं।

क्या है गवर्निंग काउंसिल व उसका काम

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो अंतर क्षेत्रीय, विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार के लिए एक प्रशासनिक मंच है, इसमें प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, प्रशासनिक परिषद के पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। इस छठी बैठक की विशेषता यह रही कि पहली बार इसमें जम्मू-कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश के रुप में भागीदारी हुई तो लद्दाख को पहली बार इसमें शामिल होने का मौका मिला।

किसी भी देश की प्रगति का आधार यही है कि केंद्र और राज्य साथ मिल कर कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को सार्थक और जिला स्तर तक प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हुए विकास को बढ़ावा दिया है। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, तो पूरा देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्मित हुई। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री के संबोधन के अहम बिंदु:

- देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। हमें इस उत्साह का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर देना है।
- केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत ढांचा और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तटीय राज्य एक अच्छा उदाहरण है। नीली अर्थव्यवस्था में निर्यात के असीमित अवसर हैं।
- सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की है। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है।
- इस साल के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध कराए गए फंड से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी बल्कि रोजगार के काफी अवसर भी पैदा होंगे।

भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने की दिशा में बढ़ते कदम

टेलीकॉम-इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत को दुनिया का विनिर्माण हब बनाने, ड्रग्स क्षेत्र में विनिर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए पीएलआई की पहल के साथ-साथ बच्चों की देखभाल और उसके हितों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार ने उठाए अहम कदम

- **फैसला: आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी।**
- **प्रभाव:** इससे घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन और आईटी हार्डवेयर की वैल्यू चेन में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे 3.3 लाख करोड़ रु. का उत्पादन होगा, 2.4 लाख करोड़ रु. (उत्पादन का 75%) निर्यात होगा। इससे प्रत्यक्ष कर राजस्व के तौर पर 1090 करोड़ रुपये मिलेंगे और करीब 1.8 लाख रोजगार के अवसर बनेंगे।
- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग में ग्लोबल हब का स्थान मिलेगा।
- 4 वर्षों में कुल लागत लगभग 7350 करोड़ रुपये। पात्र कंपनियों को 4 वर्षों के लिए भारत में निर्मित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 4 से लेकर 1% तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **फैसला: टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी।**
- **प्रभाव:** 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली इस योजना में 5 वर्ष में 12,195 करोड़ रु. खर्च होगा। इससे उत्पादन में 2 लाख करोड़ रु. से ज्यादा की वृद्धि होगी। टेलीकॉम एवं नेटवर्किंग उत्पादों को प्रोत्साहित कर निवेश को आकर्षित करेगा।
- योग्य निवेशकों को न्यूनतम निवेश सीमा के 20 गुना तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- मेड इन इंडिया टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह 50 हजार रु. से अधिक मूल्य के दूरसंचार उपकरणों के आयात की भरपाई करेगा।
- 3 हजार करोड़ रु. का निवेश होगा और बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।
- **फैसला: ड्रग्स विनिर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए फार्मा सेक्टर में पीएलआई को मंजूरी।**
- **प्रभाव:** यह योजना 2020-21 से 2028-29 के लिए होगी जिससे घरेलू दवाई विनिर्माताओं को लाभ मिलेगा और निर्यात की मात्रा बढ़ेगी। इससे जटिल और तकनीक वाले उत्पादों के विकास में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। जिससे सस्ते-सुलभ चिकित्सा उत्पाद लोगों को मिलेंगे।
- 15 हजार करोड़ रु. के निवेश और 20 हजार प्रत्यक्ष व 80 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- **फैसला: बाल संरक्षण कानूनों का सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी।**
- प्रभाव: इससे बाल संरक्षण के उपायों को मजबूती मिलेगी। मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिलाधिकारी और एडीएम भी गोद लेने के आदेशों के लिए अधिकृत होंगे।
- इस संशोधन से संकट की स्थिति में जिलाधिकारी को बच्चों के पक्ष में निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। ●

गरीब कल्याण अभियान कोरोना काल में बना सहारा

दुनिया जब कोरोना महामारी की चपेट में आई तब केंद्र सरकार ने पहली चिंता की गरीबों की। लॉकडाउन की घोषणा की गई तो साथ में इसकी भी तैयारी की गई कि इसकी वजह से कहीं किसी के घर का चूल्हा तो नहीं बुझा। इसलिए लॉकडाउन की घोषणा के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए दुनिया के सबसे बड़े गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत की, जिसने कोरोना की जंग जीतने में की देश की मदद ...

“देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से, किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए, लॉकडाउन होते ही सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री”

लॉकडाउन में जैसे उम्मीद का सूरज डूब रहा था। ऐसे में देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही कि ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई-बहन भूखा न सोए। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरा प्रयास किया और तभी उजाले की नई किरण के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान और रोजगार योजना की शुरुआत हुई। सिकंदरपुर गांव में इसी अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की शुरुआत हुई। लालो मजदूरी का काम करते थे, मनोज राजमिस्त्री और सुंदर पेंटिंग का। तीनों को वहां काम मिल गया। लालो कहते हैं कि जब घर के नजदीक ही रोजगार मिल जाए तो दूसरे प्रदेश क्यों जाना? भूखे पेट सोना क्या होता? यह वही समझ सकता है जिसने गरीबों के इस दर्द को महसूस किया हो। इसीलिए कोरोना के चलते जब ‘जान है तो जहान है’ कहते हुए

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)

- 2.76 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज।
- 42 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरुरतमंदों के खाते में सीधे नकद राशि।

मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी

मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सितंबर 2020 तक 195.21 करोड़ कार्य-दिवस सृजित किए गए। इसके अलावा, वेतन और सामग्री की लंबित राशियों का भुगतान करने के लिए राज्यों को 59,618 करोड़ रुपये जारी किए गए।

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:** इस योजना के तहत गरीबों को आठ महीने मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया गया। अप्रैल और जून 2020 के बीच 18.8 करोड़ लाभार्थियों को कुल 5.43 लाख मीट्रिक टन दाल वितरित की गई।

संगठित क्षेत्रों में कम पारिश्रमिक पाने वालों की मदद : जिन जगहों पर 100 से कम कामगारों को हर महीने 15,000 रुपए से कम वेतन मिलता था। सरकार ने जून तक उनके पीएफ खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24% भुगतान करने का प्रस्ताव किया। सरकार ने 43 लाख कर्मचारियों के खाते में 24 % अंशदान का भुगतान किया। 2476 करोड़ रुपये दिए गए।

हर संभव मदद...

- **बीमा :** सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना महामारी से लड़ रहे 22 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपये से अधिक का बीमा। इसमें सफाई कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी और तकनीशियन भी शामिल।

- **किसानों को लाभ :** पीएम किसान योजना के तहत दिसंबर 2020 तक करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में तीन बार दो-दो हजार रुपए डाले गए।

- **गरीबों को मदद :** प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाता धारक 20.65 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में तीन महीने पांच-पांच सौ रुपया दिया गया। पहली किस्त में 10,325 करोड़ रुपया, दूसरी किस्त में 20.63 करोड़ महिलाओं को 10,315 करोड़ रुपये और तीसरी किस्त में 20.62 करोड़ महिलाओं को 10,312 करोड़ रुपया जारी किया गया। इसके अलावा, पांच-पांच सौ रुपया करके दो बार में करीब 2.81 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के खाते में 2,814.5 करोड़ रुपया डाला गया। करीब 1.82 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को 4,987.18 करोड़ रुपया सहायता प्रदान की गई।

- **मुफ्त गैस सिलेंडर:** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत अप्रैल से लेकर मई 2020 तक 8.52 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर दिए गए। साथ ही, योजना के तहत जून 2020 में 3.27 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों जबकि जुलाई 2020 में 1.05 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की तो 48 घंटे के भीतर ही 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत भी कर दी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 1.75 लाख करोड़ रुपये की एक राहत पैकेज की घोषणा की। इसका उद्देश्य गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करना था। इस योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को 30 जून तक मुफ्त अनाज दिया जाने लगा। यही नहीं, जरूरत महसूस हुई तो इस योजना को फिर छठ-दीपावली तक आगे बढ़ा दिया गया। झारखंड के गिरीडीह के रामशंकर ठाकुर हों या मध्य प्रदेश के अनूपपुर के बिजुरी गांव की अनीता देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं, जिन्हें दुनिया की मुफ्त अनाज वाली इस सबसे बड़ी योजना का लाभ मिला। यह एक बड़ी योजना थी जिसकी सफलता ने दुनिया को भी हैरान और आश्चर्यचकित करके रख दिया। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त में दी गई। गरीबों को यह अनाज उन्हें पहले से मिल रहे मौजूदा कोटे के अतिरिक्त दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दो चरणों में लागू की गई। दोनों चरणों को मिला कर इस योजना में करीब-करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। ●

राष्ट्र के विकास का जरिया बन रहा है अब आम बजट

कोरोना काल के बाद पेश हुए पहले आम बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया ने देश का मिजाज बताया तो अब शीर्ष नेतृत्व के स्तर से उसे अमलीजामा पहनाने की पहल हो रही है ताकि बजट महज वित्तीय औपचारिकता नहीं, इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए हर सेक्टर अंतिम व्यक्ति तक उसकी डिलिवरी सुनिश्चित करने में जुट जाए

संसदीय इतिहास में संभवतः यह पहला मौका होगा जब आम बजट को जमीन पर शत-प्रतिशत साकार करने की दिशा में देश का शीर्ष नेतृत्व खुद हर सेक्टर से संवाद स्थापित करने को प्राथमिकता दे रहा है। इसका मकसद हर सेक्टर को इस बार के बजट की गंभीरता का अहसास कराते हुए उसे राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण उपकरण बनाना है। देश के युवा मन में एक नई आशा का संचार हो, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सेक्टर के साथ सीधा संवाद शुरू किया है और इस कड़ी में उन्होंने मुखरता के साथ विनिवेश की पैरवी की तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने, स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और किसानों से जुड़े विषयों पर वेबिनार के जरिए बात की।

प्रधानमंत्री ने गैर रणनीतिक क्षेत्र के पीएसयू के निजीकरण की वकालत की। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। बजट में घोषित सुधारों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार "मौद्रीकरण और आधुनिकीकरण" के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, जो भारतीयों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। उनका कहना था कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और उनमें से कई को सार्वजनिक धन के समर्थन की आवश्यकता है। यह अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है। उनका कहना था कि इस बजट में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का विस्तार करने और सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों को मजबूत करने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने दो-टूक कहा, "सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है क्योंकि सरकार ऐसा करने लगती है तो उसके संसाधनों का दायरा सीमित हो जाता है।"

ऐसे धन जुटाएगी सरकार

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की अवधारणा पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर सभी 100 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा है क्योंकि सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी 100 परिसंपत्तियों से 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जमाकर्ताओं और निवेशकों का विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। देश के वित्तीय सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिलकुल साफ है। इस वर्ष के बजट में भारत के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के विजन को आगे बढ़ाया गया है।"

स्वास्थ्य क्षेत्र, दुनिया का नया भरोसा भारत

स्वास्थ्य क्षेत्र पहली बार किसी बजट के केंद्र में है। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर कहाः

- स्वास्थ्य क्षेत्र में इस वर्ष का बजट आवंटन प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम चार मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा- बीमारियों को रोकना, दूसरा मोर्चा- गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ता और प्रभावी उपचार प्रदान करना है।
- तीसरा मोर्चा- हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाना है। चौथा मोर्चा- समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड में काम करना है।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की जरूरत

कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन पर पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए निजी क्षेत्र के अधिक योगदान पर जोर दिया। **उनके संबोधन के बिंदुः**

- 21वीं सदी के भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल उत्पादन के बाद खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की आवश्यकता है।
- हमें प्रसंस्कृत खाद्य के लिए देश के कृषि क्षेत्र का वैश्विक बाजार में विस्तार करना है। सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.50 लाख करोड़ कर दिया है।
- ऑपरेशन ग्रीन के तहत फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है, किसान रेल देश के लिए कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का एक मजबूत माध्यम बन गई है।

बढ़ रहा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र

भारत के पास हथियार एवं सैन्य उपकरण बनाने का सदियों पुराना अनुभव है, लेकिन देश की आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया। भारत अब अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमता को तेज गति से बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण क्षमता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। भारत ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी ऐसी 100 रक्षा वस्तुओं की सूची बनाई है जिनका स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से ही विनिर्माण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, "सरकारी भाषा में ये निगेटिव लिस्ट है, लेकिन आत्मनिर्भरता की भाषा में ये पॉजिटिव लिस्ट है।" उनका कहना था कि भारत आज अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब अपने लड़ाकू विमान तेजस की फाइल बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी कोशिश के चलते आज वह आसमान में शान से उड़ान भर रहा है। **रक्षा क्षेत्र में बजट के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर पीएम ने कही ये बातः**

- 2014 के बाद से हम रक्षा क्षेत्र के व्यापार में पारदर्शिता, संभावनाएँ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने डी-लाइसेंसिंग, डी-रेगुलेशन, एक्सपर्ट प्रमोशन, विदेशी निवेश उदारीकरण आदि के साथ कई कदम उठाए हैं।
- हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अपने सैनिकों और हमारी युवा पीढ़ी दोनों के सशक्तीकरण के रूप में देखना होगा। मैं निजी क्षेत्र से आग्रह करता हूं कि वह विनिर्माण के साथ-साथ डिजाइन और विकास के क्षेत्र में आगे आएं।
- हमारी सरकार अपने इंजीनियरों-वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर निर्भर है और आज तेजस आकाश में उड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले 48 हजार करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। ●

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें-

पर्यावरण सुरक्षा पर प्रतिबद्ध भारत

ऐसे समय जब पूरी दुनिया घटते जंगल, सिकुड़ते जल स्रोतों के साथ जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है, भारत अकेला देश है जो पैरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने में अपने हिस्से के योगदान तक पहुंच पाया है। 21 मार्च को जब हम अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और 22 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मना रहे हैं, तब यह सोचें कि केंद्र सरकार के इन प्रयासों में हम कैसे योगदान दे सकते हैं...

प्रकृति में परामात्मा' के सिद्धांत पर चलते हुए भारत में आदि काल से ही जंगल और जीवन को एक साथ एक दृष्टि से देखा जाता है। यही नहीं, भारत दुनिया में अकेला देश है, जहां आज भी नदियों को पूजा जाता है। सम्राट अशोक से लेकर महात्मा गांधी के संवादों तक, पर्यावरण और जल संरक्षण हमेशा प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित खुली बहस में भी भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संबोधन की शुरुआत शुक्ल यजुर्वेद के एक वैदिक श्लोक से की तो पर्यावरण की चिंता पर हमारी प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया ने ध्यान से सुना-

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः,
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः,
सर्वँ शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि॥

अर्थात "अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी में संतुलन होने दो! पौधों में, पेड़ों में विकास होने दो! भगवान में अनुग्रह और आत्मा में आनंद आने दो। हर चीज में संतुलन रखें और ऐसी शांति हम में से हर एक के पास हो!

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 38 लाख लोगों की मौतों का कारण वायु प्रदूषण होता है। तमाम रिपोर्ट्स और सर्वे बताते हैं कि साल दर साल जंगलों का दायरा सिमटता जा रहा है। जल स्रोत खत्म हो रहे हैं। नदियां रास्ता बदल रही हैं...और इन वजहों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इन्हीं कारणों का समाधान खोजने के लिए जब 2015 में पेरिस में दुनिया के 196 देशों ने मंथन किया। तब विकसित के साथ विकासशील देशों के लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए।

उद्देश्य था कि दुनिया के सामने खड़े इस संकट का सामना सब मिल कर करें, लेकिन आज 5 साल बाद जब इसकी रिपोर्ट

जल और जंगल...दोनों पर ध्यान

ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत टॉप 10 में शामिल है। पेरिस जलवायु समझौते की पांचवीं वर्षगांठ पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाईमेट चेंज परफारमेंस इंडेक्स 2021 में भारत टॉप 10 देशों में स्थान पाने में सफल रहा। इंडेक्स में भारत दसवें स्थान पर रहा। वर्ष 2014 में भारत 31वें स्थान पर था। यह लक्ष्य ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे बीते वर्षों की वो अथक मेहनत और दूर दृष्टि वाली सोच है, जिसके तहत भारत में जंगलों का दायरा बीते चार साल में 13 हजार किमी बढ़ा है।

8,07,276

वर्ग किमी भारत में कुल वन और जंगल है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2019 के अनुसार

- स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में पहली बार 2019 में भारत में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरु किया गया। इसके तहत वर्ष 2024 तक हवा में पाए जाने वाले हानिकारक कण पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा को 30% तक कम करना है।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस-4 के बाद सीधे बीएस-6 मानक को लागू किया गया तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की गई।
- उजाला, स्वच्छ भारत और नमामि गंगे जैसी योजनाएं पर्यावरण के साथ जल संरक्षण की दिशा में अहम साबित हो रही हैं। नमामि गंगे योजना के तहत 305 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण की विशेष योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है तो समुद्र तंत्र को बचाने के लिए प्लास्टिक को खत्म करने और जलीय जीवों के संरक्षण नीति की शुरुआत की गई है।
- जंगलों को बचाने के लिए अक्षय ऊर्जा की दिशा में दुनिया के देशों में सबसे प्रभावी कदम भारत ने ही उठाए हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के तय लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा।
- 31 नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है।

- **देश में वन और जंगल की स्थिति में वर्ष 2017 की तुलना में 5,188 वर्ग किमी. की वृद्धि (0.65 प्रतिशत) हुई है।**
- **देश में कुल जंगल 7,12,249 वर्ग किमी. है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 प्रतिशत है।**
- **कर्नाटक में वन क्षेत्र में 1025 वर्ग किमी. की सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसके बाद आंध्र प्रदेश (990 वर्ग किमी.), केरल (823 वर्ग किमी.) जम्मू एवं कश्मीर (371 वर्ग किमी.) और हिमाचल प्रदेश (334 वर्ग किमी.) है।**
- **लकड़ी के पारंपरिक ईंधन के बजाय घरों में एलपीजी के उपयोग के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई। इसके तहत अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं।**

सामने आई तो तय लक्ष्य को हासिल करने वाला भारत अकेला देश है।

यह तमाम प्रयास पिछले 6 साल में जल और जंगल के संरक्षण की दिशा में एक बानगीभर हैं। केंद्र सरकार की पर्यावरण संरक्षण संबधित चिंताओं को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर के जरिए आसानी से समझ सकते हैं, जब तमिलनाडु के मामल्लपुरम समुद्र तट पर खुद कचरा बीन कर उन्होंने प्रकृति की सुरक्षा का संदेश दिया था। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण सुरक्षा के इस प्रयास में अपना योगदान जरूर दें। ●

खुले स्कूल
खिलखिला उठे बच्चों के चेहरे

कोरोना की आपदा 21वीं सदी के छात्रों के लिए एक ऐसा अहसास है जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। 11 महीनों तक घरों में बंद रहकर ऑनलाइन पढ़ाई को मजबूर छात्रों का जीवन अब सामान्य हो रहा है क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ स्कूल-कॉलेज खुलने लगे हैं। स्कूल में दोस्तों के साथ मौज-मस्ती, खेल-कूद के साथ छात्र एक बार फिर खुली हवा में नई उड़ान भरने को है तैयार

कोरोना की वजह से इतने लंबे समय तक घर की चारदीवारी में बिताकर मैं जब स्कूल पहुंची और दोस्तों के साथ स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया तो मुझे लगा कि यह मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। कोरोना काल में सब कुछ बंद था और पढ़ाई भी ऑनलाइन तक सीमित थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक बार फिर पुराने दिन लौट आए हैं।" यह कहना है पटना की ज्योति का जो देहरादून के एक आवासीय विद्यालय 'द इंडियन पब्लिक स्कूल' की छात्रा है। वह बीते फरवरी में स्कूल पहुंची तो घर से कोरोना के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई थी, लेकिन स्कूल ने एक बार फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया। उसके बाद छात्रों को एक सप्ताह के लिए क्वारंटीन रखा गया जहां खाना से लेकर सारी चीजें कमरे में ही पहुंचाई जा रही थी। शुरुआत में अजीब महसूस हुआ लेकिन अब उसे लग रहा है कि 11 महीने बाद फिर वही दिन लौट आए हैं। नागालैंड का वज्रदीपन भी कहता है कि इतने समय बाद मोबाइल से निकलकर वास्तविक दुनिया में कदम रखना एक सुखद अहसास है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का शार्दुल बताता है कि कैसे वह दिन भर स्क्रीन से पढ़ाई करने से बोर और बिलकुल बेजान महसूस करता था। लेकिन अब स्कूल लौटकर फुटबॉल के मैदान में गेंद उछालने के साथ ही मेरा मन भी कुलांचे भरने लगा है। ऐसी ही कहानी देश के आवासीय ही नहीं, अन्य स्कूलों की भी है।

आयुष केडिया गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वह बाल भारती पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 वीं में पढ़ते हैं। अब आयुष का स्कूल भी खुल गया है जो कोरोना के कारण लंबे समय तक बंद था। अब नियमित तौर पर कक्षा में भाग ले रहे आयुष फिर से स्कूल खुलने पर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं, "11 महीने बाद स्कूल खुलने पर काफी खुशी हुई। ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पा रही थीं और दोस्तों से भी मिलना

कोरोना काल में बदले स्कूलों के नियम

- शिक्षा मंत्रालय ने 'निष्ठा' नामक कार्यक्रम लागू किया। यह एक ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसमें देश के सभी 42,00,000 प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक और प्रचार्य शामिल हैं।
- लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) ने अपने शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई पर प्रशिक्षण देने का व्यापक प्रयास किया। इस प्रक्रिया में, पूरे देश में सीबीएसई ने 4,80,000 शिक्षक, केवीएस ने 15,855 शिक्षक और जेएनवी ने 9,085 शिक्षक प्रशिक्षित किए गए।
- सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक स्तर पर नौवीं कक्षा में एक नए विषय की शुरूआत की है जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। केवीएस में छात्रों में शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में बताने के लिए फिटनेस प्रशिक्षण और योग पर ऑनलाइन सत्र का आयोजन।
- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने एक पहल की शुरूआत की है। इसका नाम है 'मनोदर्पण'। इसमें कोरोना प्रकोप के दौरान और उसके बाद छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर मानसिक और सामाजिक सहायता देने के लिए कई गतिविधियां शामिल।
- डिजिटल पहुंच को आसान बनाने के लिए 34 डीटीएच टीवी चैनलों के एक समूह- स्वयं प्रभा और सामुदायिक रेडियो सहित रेडियो का व्यापक रूप से उपयोग। इनकी मदद से, दूरस्थ क्षेत्रों में भी छात्रों को 24X7 शिक्षा प्रदान करने में मिली सफलता।
- 'दीक्षा' पर उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री अब 'स्वयं प्रभा' टीवी चैनल के माध्यम से उपलब्ध। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल का मतलब उन छात्रों को सहायता प्रदान करना है जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। इसके जरिए 1 करोड़ 60 लाख छात्रों ने 3,605 पाठ्यक्रम पूरे किए। शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए 'ज्ञान' के जरिए 58 देशों के 800 प्रोफेसरों द्वारा 2101 कोर्स का संचालन किया गया।
- पिछले कुछ वर्षों में उत्कृष्ट डिजिटल शैक्षिक सामग्री तैयार की गई। ये दीक्षा, स्वयं, वर्चुअल लैब, ई–पीजी पाठशाला और नेशनल डिजिटल लाईब्रेरी जैसे विभिन्न प्लेटफार्म पर उपलब्ध।
- हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में कुल मिलाकर लगभग 2,000 ऑडियो-रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

नहीं हो पाता था। यह सब लंबे समय से बंद था जिसके कारण काफी परेशानी होती थी। अब शिक्षकों और दोस्तों से मिलना हो पाता है जिससे पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों में भी काफी मदद मिल रही है। मैं इन सब चीजों को काफी मिस कर रहा था।" कोरोना के लॉकडाउन ने सबसे अधिक बालमन को ही प्रभावित किया था। लेकिन अब जब सरकारी निर्देश के बाद प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुलने लगे हैं तो बच्चों के खिले हुए चेहरे और मुस्कान यह बता रही है कि जीवन पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि, शिक्षा पर इस आपदा का असर नहीं पड़े, इसके लिए भी कोरोना काल में केंद्र सरकार ने पूरे बंदोबस्त किए थे। छात्रों तक पहुंचने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल साधनों से शिक्षा का सफर थमने नहीं दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिजिटल संसाधनों ने पहुंच बनाई और पीएम ई-विद्या जैसी व्यापक पहल की गई। जिन क्षेत्रों में या बच्चों तक इंटरनेट की पहुंच सहज नहीं थी, उसके लिए भी डीटीएच के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित किया गया। ●

टीकाकरण अभियान
अब चढ़ने लगा इंद्रधनुषी रंग

भारत जैसे विस्तृत भूभाग वाले देश में जीवन सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे में कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण एक बहुत ही कारगर तरीका है। हालांकि, यह एक बहुत ही खर्चीला तरीका है। साथ ही समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अशिक्षा, संवाद की कमी का सामना कर रहा है। रूढ़िवादिता और कठिन भौगोलिक स्थिति कुछ अन्य चुनौतियां हैं, जिसके कारण लोग टीकाकरण में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ऐसे में इस सोच को समाप्त करने के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े ...

असम के धुबरी जिले में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर ईंट भट्ठे में काम करने वाले नयन अपने बच्चों को टीका दिलाने के लिए नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इससे उनकी दिहाड़ी मारी जाती। बार-बार के प्रयासों के बाद भी माता-पिता अपने बच्चों को टीका केन्द्र पर ले जाने के प्रति अनिच्छुक थे। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मजदूरों के कार्य स्थल पर जाकर बच्चों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया और करीब 30 बच्चों का टीकाकरण किया। असम के चिरांग, मोरीगांव और लखीमपुर में भी ऐसी ही स्थिति थी, जिसे मिशन इन्द्रधनुष से सुधारा गया था। लखीमपुर में विशेष टीकाकरण अभियान से 99 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने में सफलता मिली थी।

खतरनाक बीमारियों से जीवन को बचाने के लिए टीकाकरण अब तक का सबसे प्रभावी तरीका साबित हुआ है। सरकार जनता के डर को दूर करने और टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाना उसी पहल का एक अहम हिस्सा है। असल में 16 मार्च वो दिन है जिस दिन देश में पहली बार पोलियो टीके की खुराक पिलाई गई थी। पल्स पोलियो एक बहुत बड़ा अभियान था, जिसके तहत पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो टीके की दो बूंदें पिलाई गई। व्यापक पैमाने पर शुरू किए गए इस टीकाकरण अभियान का परिणाम है कि 27 मार्च, 2014 को भारत को 'पोलियो-मुक्त प्रमाण पत्र' प्राप्त हुआ। पल्स पोलियो अभियान की 'दो बूंद जिंदगी की' टैगलाइन अभी भी जनता के दिलो-दिमाग में बसी हुई है।

मिशन इन्द्रधनुष

भारत तीन दशकों से अधिक समय से टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है, बावजूद इसके 2014 तक केवल 65 प्रतिशत बच्चों का ही टीकाकरण किया जा सका था। इसका मतलब है कि लगभग 89 लाख बच्चों का टीकाकरण नहीं हो सका था। असंक्रमित और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चे बचपन में होने वाली बीमारियों और विकलांगता के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। टीकाकरण नहीं कराने वाले बच्चों में संक्रामक बीमारियों से मृत्यु का जोखिम तीन से छह गुना अधिक रहता है। टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए सरकार ने कई गहन रणनीतियों पर अमल किया है और इसीलिए वर्ष 2014 में शुरुआत हुई 'मिशन इन्द्रधनुष' की। इसका उद्देश्य निर्धारित किए गए महीनों के दौरान विशेष अभियान के जरिए टीकाकरण कवरेज को तेजी से आगे बढ़ाना है। मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत निर्धारित किए गए सभी टीके दो साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं। मिशन इन्द्रधनुष के पहले दो चरणों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इन्टेन्सफाइड मिशन इन्द्रधनुष (आईएमआई) 2017-18 में लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद, पूर्ण टीकाकरण कवरेज में औसतन 18.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 23 फरवरी, 2021 तक मिशन इन्द्रधनुष के तहत कुल 3,76,00,000 बच्चों का टीकाकरण किया गया था।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूनिवर्सल इन्युनाइजेशन प्रोग्राम) डिप्थीरिया और बचपन में होने वाले टीबी के गंभीर रूप वाली बीमारियों को लक्षित करने वाला एक टीकाकरण अभियान है।
- यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है। यूआईपी टीकाकरण के जरिए पांच साल से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने में काफी हद तक प्रभावी है। यूआईपी के तहत सालाना 2.67 करोड़ नवजात और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर इन बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। वे बीमारियां हैं- डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, चेचक, खसरा, बचपन में होने वाला टीबी, हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला निमोनिया।
- रोटावायरस, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस का टीका कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है। यूआईपी की प्रमुख उपलब्धियां हैं - 2014 में पोलियो का उन्मूलन, 2015 में मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन (एमएनटीई) और चेचक का उन्मूलन।

यूआईपी के तहत नए टीके

- **इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी):** आईपीवी दुनिया भर से पोलियो उन्मूलन रणनीति का हिस्सा है। आईपीवी को नवंबर 2015 में 6 राज्यों में शुरू किया गया था और अप्रैल 2016 तक पूरे देश में इसका विस्तार किया गया था।
- **रोटावायरस वैक्सीन (आरवीवी) :** रोटावायरस डायरिया के कारण मृत्यु दर और बीमारी को कम करने के लिए मार्च 2016 में आरवीवी शुरू किया गया था।
- **खसरा रूबेला (एमआर) वैक्सीन :** खसरा उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण के लिए 2017 में एमआर वैक्सीन टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में शुरु किया गया था।
- **न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पीसीवी) :** न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर और बीमारी को कम करने के लिए मई 2017 में पीसीवी लॉन्च किया गया था। आम बजट 2021-22 के प्रावधानों के अनुसार, यह 'मेड इन इंडिया' उत्पाद है, जो इस समय सिर्फ 5 राज्यों में दिया जा रहा है और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों को मौतों से बचाया जा सकेगा।
- **टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन :** यूआईपी में टीडी वैक्सीन की जगह टीटी वैक्सीन दिया जाता है।

हर हिन्दुस्तानी इस बात पर गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60 % बच्चों को जो जीवनरक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

एक टीका भरोसे का

कोरोना महामारी की जंग में भारत की भूमिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे अहम माना है। पहले दौर में स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद अब टीकाकरण के सबसे महत्वपूर्ण दौर आम जन से हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवा कर दिया जनता को संदेश...

भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोवीशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन की डोज दी जा रही है। टीकाकरण की शुरुआत में कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को टीका लगावाकर इन सारे सवालों का जवाब दिया। वैक्सीन लगवाने के लिए एम्स दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री असम का पारंपरिक गमछा रखे हुए थे। इसे महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने उन्हें वैक्सीन लगाई।

मैं वैक्सीन लेने के सभी पात्र व्यक्तियों से वैक्सीन लेने का अनुरोध करता हूं। आइए, हम मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। —नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है। पहले चरण में 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने के बाद 1 मार्च से 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर मरीज और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। टीकाकरण के दूसरे दौर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीका लगवाकर की। 12000 सरकारी अस्पतालों में यह टीका मुफ्त है तो इतने ही निजी अस्पतालों में मात्र 250 रुपये में लगाया जा रहा है। निजी अस्पतालों में 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा दी गई है। उधर, अरुणाचल प्रदेश अब कोरोना मुक्त हो गया है। राज्य में 28 फरवरी तक कुल 16, 836 मरीज मिले थे। जिनमें से 56 मरीजों की मृत्यु हो गई, जबकि 1 मार्च तक बाकी सभी मरीज पूर्णतः स्वस्थ्य हो चुके हैं। यहां अब कोरोना का कोई मामला नहीं है। हालांकि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है।

दवाई भी, कड़ाई भी

1,80,05,503 कुल टीकाकरण	**21,99,40,742** कुल जांच की गई
1,76,319 सक्रिय मामले	**1,08,39,894** लोग स्वस्थ हुए
97.01% रिकवरी रेट	

मृत्यु दर (1.41%) (नोट- आंकड़े 4 मार्च तक)

वैक्सीन मैत्री: 48 देशों को 4.61 करोड़ से ज्यादा डोज भेजीं, डब्ल्यूएचओ ने कहा-भारत से सीखें

- **वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 3 मार्च तक भारत 48 देशों को वैक्सीन के 4 करोड़ 61 लाख 66 हजार डोज भेज चुका है। इनमें से 71 लाख 25 हजार डोज उपहार के रूप में भेजी गई हैं।**
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया एडेहनम ग्रेब्रेयेसस ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि कई देशों में भारत की मदद के जरिए टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को भी इस मामले में भारत से सीख लेनी चाहिए।**

प्रधानमंत्री का छात्रों को मंत्र

सेल्फ थ्री

सेल्फ अवेयरनेस
सेल्फ कांफिडेंस
सेल्फलेसनेस

राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ छात्रों को अपने सामर्थ्य की पहचान करने, आत्मविश्वास और निःस्वार्थ भाव (सेल्फ थ्री) से आगे बढ़ने का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती और आआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि फैसला लेने से नहीं हिचकें क्योंकि राष्ट्र प्रथम की सोच से लिया गया हर फैसला किसी न किसी समाधान की ओर लेकर जाता है। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया। 19 फरवरी को विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में 2535 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई।

आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी के संबोधन के अहम बिंदु

- सरकार ने मैप और भू-स्थानिक डाटा को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। इस कदम से देश के युवा स्टार्टअप और इनोवेटर्स को नई आजादी मिलेगी। भारत की आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित 75 बड़े इनोवेशन को संकलित कर दुनिया के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- कैंपस से निकलकर छात्रों को नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव करने वाला एक स्टार्ट अप भी बनना है। ये डिग्री, ये पदक, करोड़ों की उम्मीदों का एक आकांक्षा पत्र है।
- एक इंजीनियर होने के नाते आप में चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता है। चाहे आईटी हो या मॉडर्न कंस्ट्रक्शन तकनीक या कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, आईआईटी खड़गपुर प्रशंसनीय काम कर रहा है।

विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी के संबोधन के अहम बिंदु:

50,000 **करोड़ रु. का प्रस्ताव बजट में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है।**

- बंगाल एक भारत-श्रेष्ठ भारत के लिए एक प्रेरणा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब विश्व भारती के 25 बड़े लक्ष्य क्या होंगे? इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए।
- विश्व भारती 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारतीय ज्ञान तथा पहचान को विश्व के कोने-कोने तक ले जाएगा।
- शिक्षा नीति में जेंडर इनक्लूजन फंड का प्रावधान है जिससे लड़कियों को नया विश्वास प्राप्त होगा। ●

आईआईटी खड़गपुर में प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

खेल-खेल में ज्ञान और संदेश

खेल और खिलौना भारतीय संस्कृति का अहम हिस्से रहे हैं। खेल के साथ-साथ बच्चों को सीख देने वाला खिलौना मिले तो भला क्या कहने। अब देश में ऐसे ही खिलौने बन रहे हैं जो खेल-खेल में बच्चों का ज्ञान तो बढ़ाएंगे ही, उन्हें भारत की प्राचीन संस्कृति, इतिहास, कला से भी रूबरू कराएंगे...

केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने बनाए अनोखे खिलौने

देश के पहले खिलौना मेले में राजधानी दिल्ली के ओल्ड जेएनयू स्थित केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को जगह मिली तो उसकी वजह उनका हुनर और ज्ञान रहा। यहां के छात्रों ने कठपुतली के जरिए अलग-अलग विषयों को समझाने का प्रयास किया है। इससे खेल-खेल में कठिन विषयों को आसान तरीके से सीख सकते हैं। इसे बनाने वाली छात्राओं का कहना है, " इस कठपुतली के जरिए जो भी पाठ होते हैं, वो बिलकुल सजीव लगते हैं। यह आसानी से समझ में आ जाते हैं। आजकल बच्चे पश्चिम की संस्कृति की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन इस प्रकार के खेल के माध्यम से हम उन्हें भारत की प्राचीन संस्कृति, इतिहास और कला के बारे में बता सकते हैं। इससे मनोरंजन के साथ ज्ञान भी मिलेगा।" बच्चों के इस हुनर और हौंसलों से उत्साहित प्रिंसिपल सुदीप बाजपेयी कहते हैं, "अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो स्कूल बच्चों के लिए बोरियत भरी नहीं, बल्कि आनंद देने वाली एक जगह बन जाएगा। यही भारत की नई शिक्षा नीति का पहला अध्याय भी है। बच्चे खेल-खेल में सब कुछ सीख सकेंगे। शायद इनकी सीखने की क्षमता और पद्धति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।" ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस खिलौने मेले से बच्चों के मानसिक बौद्धिक विकास के साथ तमाम उद्यमियों को भी सार्थक मंच मिला है। ●

सांप-सीढ़ी का खेल सिखा रहा कोरोना प्रोटोकॉल

मध्य प्रदेश के इंदौर के समीर कुमार ने कोरोना से जुड़ा लूडो गेम बना कर संक्रमण से बचाव का संदेश दिया है। इसमें खेल के जरिए यह जान सकते हैं कि किस गतिविधि से कोरोना से बचाव होगा और किससे इसका संक्रमण बढ़ेगा। अपने इस गेम की बदौलत समीर को देश के पहले खिलौना मेले में प्रवेश तो मिला ही, साथ ही इस गेम ने रोचकता भी पैदा की। समीर बताते हैं, "इसमें हम पासा फेंकते हैं और पासे में जो अंक आता है उससे खिलाड़ी आगे चलता है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन, सैनेटाइजर का इस्तेमाल, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करें, इसी रोचकता को बढ़ाने के लिए हमने ये गेम बनाया है।" समीर ने इस लूडो गेम को सांप-सीढ़ी गेम की तर्ज पर विकसित किया है। जिसमें विभिन्न खाने बने हुए हैं। इसमें पासा फेंकने पर जो नंबर आएंगे उस नंबर के खाने के कोरोना से संबंधित सारी जानकारी खिलाड़ी को देनी होती है। इसके अलावा समीर ने टचलैस फ्रेशनर, डिस्पेंसर, लो कॉस्ट ऑटोमेशन मशीन और न्यूमेटिक ट्रेनिंग किट भी बनाए हैं जो इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है। समीर का कहना है कि मेले में बहुत सारे घरेलू-विदेशी खरीददार आए, जिससे हमें बहुत मदद मिल रही है। खिलौना क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होगा तो ऐसे रोचक उत्पाद बनेंगे और बिकेंगे जिससे समीर जैसे लोगों और देश को भी फायदा होगा। ●

Narendra Modi

खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास Tradition भी है और Technology भी।

भारत के पास Concepts भी है, और Competence भी।

हम दुनिया को Eco-Friendly Toys की ओर वापस लेकर जा सकते है।

हमारे Software Engineers Computer Games के जरिए भारत की कहानियों को दुनिया तक पहुंचा सकते है।

Rajnath Singh

दो साल पहले लागू की गई पीएम किसान सम्मान योजना ने भारत के किसानों को संबल और आत्मबल दिया है। इससे छोटे किसानों को बड़ी राहत मिली है और किसान कल्याण को सार्थक स्वरूप मिला है। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi एवं कृषि मंत्री को धन्यवाद एवं आभार।
#KisanKaSammanPMKisan

Amit Shah @AmitShah

स्पोर्ट्स एन्क्लेव व नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही खिलाड़ियों और उनके कोचों के रहने की व्यवस्था भी है।

तीन जिलों के लगभग 650 स्कूल जिनके पास अपना खेल ग्राउंड नहीं है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़ेंगे जिससे उन स्कूलों के बच्चों को खेलने की सुविधाएं मिल पाएंगी।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस साल सड़क निर्माण में एक नया इतिहास रचा है। इस वित्त वर्ष में अब तक रिकॉर्ड 11,035 किमी सड़कों और राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जो कि हर दिन 33 किमी है। यह देश में अब तक बनी सड़कों एवं राजमार्गों की सबसे तेज रफ्तार है।

With over 1,000 exhibitors coming to the Fair to showcase their products from across the country, join in to explore the world of Indian Toys by visiting theindiatoyfair.in!
Let's come together to make India #AatmaNirbhar #TheIndiaToyFair #Vocal4LocalToys

11 Partner States
85 Clusters
100+ Speakers & Experts
1000+ Companies
30000+ Toy Manufacturing Units
21 lakh+ Registrations
Children, Teachers, Parents & other stakeholders

दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम पर, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की अपील

खिलौना उद्योग में छिपी देश की ताकत

जम्मू-कश्मीर को बनायेंगे शीत खेलों का गढ़ : मोदी

स्टार्टअप की जरूरतों का ध्यान रखें बैंक

प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
16-31 मार्च 2021

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर -
DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC,
Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 5 मार्च 2021, कुल पृष्ठ-44)

आज हर बच्चा सांप-सीढ़ी के खेल के बारे में जानता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतीय पारंपरिक खेल का ही रूप है, जिसे मोक्ष पाटम या परमपदम कहा जाता है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

संपादक:
जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश, प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-
110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट
लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल
एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20